

CHARMINAR®
PAINT BRUSH
Cell : 9440297101

THE LARGEST CIRCULATED AND READ HINDI DAILY IN TELANGANA & ANDHRA PRADESH

स्वतंत्र वार्ता



epaper.vaartha.com

Ghar Ka Doctor
MY Dr. Headache Roll On
HEADACHE GONE WITH MY DR ROLL ON
100% प्रभावी
BUY NOW AT ₹35/-
For Trade Enquiry : 8919799808 www.mydrpoinrelief.com

वर्ष-28 अंक : 107 (हैदराबाद, निजामाबाद, विशाखापट्टणम, तिरुपति से प्रकाशित) श्रावण कृ. 2 2080 बुधवार, 5 जुलाई 2023

प्रधान संपादक - डॉ. गिरिश कुमार संघी हैदराबाद नगर पृष्ठ : 16 : 8 रुपये

चार राज्यों में भाजपा के नए अध्यक्ष

चुनावी राज्य तेलंगाना में जी किशन रेड्डी, कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ पंजाब संभालेंगे

नई दिल्ली, 4 जुलाई (एजेंसियां)। देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा और अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में बदलाव हुआ है। कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को पंजाब, आंध्र प्रदेश में डी पुरदेश्वरी, तेलंगाना जी किशन रेड्डी और झारखंड में बाबू लाल मरांडी को पार्टी की कमान सौंपी गई है।

इसके अलावा पार्टी हाईकमान ने एटला राजेंद्र को तेलंगाना में भाजपा के चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तेलंगाना में इसी साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी को राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य मनोनित



भाजपा ने बदले प्रदेश अध्यक्ष

- जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी
- पूर्व कांग्रेस नेता सुनील कुमार जाखड़ पंजाब के नए प्रदेश अध्यक्ष
- डी. पुरदेश्वरी को बनाया आंध्र प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष
- बाबूलाल मरांडी संभालेंगे झारखंड की कमान

किया गया है। किरण इसी साल अप्रैल में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। विधायक इटला राजेंद्र को तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों की प्रबंधन समिति के चेयरमैन बनाया है।

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ : सुनील जाखड़ 2017 से 2021 तक कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले साल मई में उन्होंने भाजपा जॉइन

की थी। वे पंजाब में अखिलेश शर्मा की जगह अध्यक्ष बनाए गए हैं। 2002-2017 तक जाखड़ अबोहर विधानसभा सीट से लगातार तीन बार विधायक भी रह चुके हैं।

>14

मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत

झारखंड हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक रांची, 4 जुलाई (एजेंसियां)। मानहानि मामले में मुश्किलों में फंसे राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। दरअसल हाईकोर्ट ने मंगलवार चार जुलाई को सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट अब 16 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करेगा। बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक में जनसभा के दौरान अपने एक बयान में कहा था कि सभी चोरों का सरगम मोदी ही क्यों है? राहुल गांधी के बयान के बाद उनके खिलाफ देश में अलग-अलग जगह मानहानि के मुकदमे दर्ज हुए थे।

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका दायर करने वाले प्रदीप मोदी को जवाब पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने राहुल गांधी को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा : मोदी

नई दिल्ली, 4 जुलाई (एजेंसियां)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई को-ऑपरेशन समिट (एससीओ) की वर्युअल समिट को होस्ट कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा, कुछ देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ये क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने ईरान के



एससीओ में शामिल होने की घोषणा भी की। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और देश की जनता को इसके लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत का सिद्धांत पूरा विश्व एक परिवार है।

हम एससीओ को भी अपना परिवार मानते हैं।

एससीओ समिट को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। पुतिन बोले, हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की अप्रोच का समर्थन करते हैं। हम एससीओ में शामिल देशों के साथ लगातार अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए काम करते रहेंगे।

पुतिन ने कहा, हम पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए जा रहे प्रतिबंधों का सामना करते रहेंगे।

>14

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जे.पी. नड्डा जी द्वारा सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी जी को तेलंगाना राज्य के भाजपा अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। साथ ही श्री इटला राजेन्द्र जी को भाजपा तेलंगाना के चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरपर्सन के रूप में मनोनीत किया।

*** शुभकामनाओं सहित ***

अमित राठी **गोविन्द राठी** **सुमित राठी**

भाजपा नेता | निदेशक : महेश वैक

RATHI INVESTMENT & FINANCIAL CONSULTING PVT. LTD.

Glow like Gold, this Ashada

This Ashada, Malabar Gold and Diamonds brings you beautiful jewellery that matches your radiance. May you and your moments shine brighter than ever with the purest and finest gold from Malabar Gold and Diamonds.

MALABAR FAIR PRICE PROMISE
For Everyone. Every day. Everywhere.
VALUE ADDITION 4.9% ONWARDS

MALABAR GOLD & DIAMONDS
CELEBRATE THE BEAUTY OF LIFE

ASHADA SHUBH LABHA

VALUE ADDITION 4.9%	VALUE ADDITION 4.9%
VALUE ADDITION 5.9%	VALUE ADDITION 13.9%
VALUE ADDITION 12.9%	VALUE ADDITION 14.9%

GET 100% EXCHANGE VALUE ON 22KT OLD GOLD.
Bring your old gold (Hallmarked or non-hallmarked) purchased from any jeweller and exchange it with Malabar HUID hallmarked products

FREE SILVER COIN WITH EVERY PURCHASE
OFFER VALID TILL 23RD JULY, 2023

Call: 1800 572 0916, 040 68138916

BUY ONLINE AT: malabargoldanddiamonds.com
INDIA | UK | USA | SINGAPORE | MALAYSIA | UAE | QATAR | KSA | OMAN | KUWAIT | BAHRAIN

आदिवासी क्षेत्रों को यूसीसी के दायरे से रखा जा सकता है बाहर

विधि आयोग को अबतक मिल चुके हैं 19 लाख सुझाव

नई दिल्ली, 4 जुलाई (एजेंसियाँ)। पूर्वोत्तर राज्यों समेत देश के कुछ हिस्सों में आदिवासी समूहों को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे से बाहर रखने पर विचार किया जा सकता है। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को अपनी अध्यक्षता वाली कानून व न्याय संबंधित संसदीय समिति की बैठक में यह विचार रखा। इस बैठक में यूसीसी के स्वरूप को लेकर शुरुआती चर्चा करते हुए उनकी राय ली गई। बैठक में विधिमन दलों के 17 सांसद एवं विधि आयोग के सदस्य शामिल थे। सबका राय के आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी, जिसे संसद में पेश किया जाएगा।

बसपा एवं शिवसेना उद्धव गुट ने यूसीसी का किया समर्थन
विधि आयोग के प्रतिनिधियों ने बताया कि अब तक यूसीसी पर 19 लाख सुझाव मिल चुके हैं। अंतिम लिथि 13 जुलाई तक यह संख्या लगभग 25 लाख तक पहुंच जाने की उम्मीद है। सुशील मोदी ने अपने सुझाव में पूर्वोत्तर एवं अन्य आदिवासी क्षेत्रों को प्रस्तावित यूसीसी के दायरे से अलग रखने की बात करते हुए कहा कि सभी कानूनों में अपवाद होते हैं।

देश में पहले से भी कई कानून हैं, जिनमें उन्हें कुछ रियायत मिली हुई है। कई कानून ऐसे भी हैं, जिनमें पूर्वोत्तर राज्यों में की सहमति के बिना वहां लागू नहीं होते है। बैठक में तुणमूल कांग्रेस



का कोई सदस्य नहीं आया, जबकि कांग्रेस एवं डीएमके समेत विपक्ष के कुछ सदस्यों ने प्रस्तावित यूसीसी को चुनवी फायदे के लिए बताया और कहा कि इस विवादित विषय पर विमर्श का अभी यह उचित समय नहीं है। बसपा एवं शिवसेना उद्धव गुट ने यूसीसी का समर्थन किया। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने भी विरोध नहीं किया, लेकिन समर्थन भी नहीं किया। शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि कई देशों में यह कानून है। विभिन्न समुदायों एवं

क्षेत्रों की व्यापक चिंता एवं विमर्श के बाद ही इसपर विचार किया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा एवं डीएमके सांसद पी विल्सन ने अपने लिखित बयान में यूसीसी पर सुझाव आमंत्रित करने के लिए विधि आयोग के कदम पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पिछले आयोग ने यूसीसी को जरूरी नहीं बताया था।

रिपोर्ट पर बनेगा कानून का नया फ्रेमवर्क
यूसीसी पर बने पिछले आयोग की 75 हजार सुझाव मिले थे,

जिसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार भी कर ली गई थी। उसमें कई तरह की विसंगतियों का जिक्र किया गया था, जिसके बाद महसूस किया गया कि यूसीसी पर नए तरीके से विचार किया जाए। अब नए सुझावों के आधार पर विधि आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार के पास अनुशंसा करेगा, जिसे कानून का रूप देने के लिए संसद में पेश किया जाएगा। इसके पहले जरूरत पड़ी तो संसदीय समिति की और बैठकें भी हो सकती हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जून को मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि अलग-अलग नियमों से परिवार नहीं चलता। उसी तरह दोहरी कानून व्यवस्था से देश नहीं चल सकता। हमारा संविधान भी सबको समान अधिकार की गारंटी देता है।

डीईआरसी चेयरमैन के शपथ ग्रहण पर अगली सुनवाई तक लगाई गई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एलजी को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली, 4 जुलाई (एजेंसियाँ)। राजधानी में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट्री कमीशन (डीईआरसी) चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर विवाद लगातार जारी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद फिलहाल दिल्ली में डीईआरसी अध्यक्ष के शपथ पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। तब तक शपथ ग्रहण पर रोक जारी रहेगी। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 7 जुलाई को होने जा रहे शपथ ग्रहण कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की थी।

क्या है दिल्ली सरकार का तर्क
इस मामले में दिल्ली सरकार की दलील है कि एलजी ने अपनी तरफ से जस्टिस उमेश कुमार को इस पद पर नियुक्त कर दिया है। यह नियुक्ति लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के कामकाज में सीधा दखल है। दिल्ली सरकार के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जनवरी में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जज राजीव कुमार श्रीवास्तव को इस पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजा था। लेकिन उन्होंने नियुक्ति का आदेश जारी नहीं किया। 15 जून को जस्टिस श्रीवास्तव ने इस पद के लिए असमर्थता जता दी। इसके बाद एलजी ने जस्टिस उमेश कुमार की नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र ने 19 मई को अध्यादेश लाकर जीएनसीटीडी एक्ट में

बदलाव कर दिया है। बदले हुए एक्ट की धारा 45-डी के तहत यह नियुक्ति की गई है। सिंघवी की मांग थी कि कोर्ट इस नियुक्ति की वैधानिकता पर सुनवाई करे। तब तक 7 जुलाई को होने जा रहे डीईआरसी अध्यक्ष के शपथ ग्रहण कार्यक्रम पर रोक लगा दी जाए।
मुफ्त बिजली बंद करने की साजिश
सिंघवी ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। उसने लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी है। अपना डीईआरसी अध्यक्ष बना कर एलजी मुफ्त बिजली बंद करना चाहते हैं। एलजी कार्यालय के लिए पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इसे आधारहीन बयान बताते हुए विरोध किया। मेहता ने कहा कि जस्टिस उमेश कुमार की नियुक्ति के मामले में दिल्ली सरकार को पूरी जानकारी थी।
एलजी दफ्तर की तरफ से दिया गया जवाब

पैसे ने बनाया हैवान

तुषार मेहता ने कहा कि जब सरकार के पृष्ठने पर जस्टिस उमेश कुमार ने 26 जून को शपथ ग्रहण के लिए सहमत दे दी, तब इन्होंने याचिका दाखिल कर दी। एक पूर्व जज के साथ ऐसा खेल अशोभनीय है। सॉलिसीटर जनरल ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देना चाहती है। उससे पहले उसके एक हिस्से (सेक्शन 45-डी) के आधार पर जारी आदेश के अमल पर रोक हासिल कर तैयारी कर रही है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने माना कि मामले को आगे सुने जाने की जरूरत है। जजों ने मंगलवार, 11 जुलाई को अगली सुनवाई की बात कहते हुए केंद्र सरकार और एलजी कार्यालय को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि तब तक डीईआरसी अध्यक्ष का शपथ ग्रहण रुका रहेगा।

राज्य पुलिस सेवा के 14 अधिकारी बने आईपीएस, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

भोपाल, 4 जुलाई (एजेंसियाँ)। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के 14 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अर्वाइ किया है। इनमें से आठ अधिकारियों को वर्ष 2021 और छह अधिकारियों को वर्ष 2022 की चयन सूची में रखा गया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे पहले भारत सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 27 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईपीएस) अर्वाइ किया था। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार 2021 की चयन सूची में मनीष खत्री, सुनील कुमार मेहता, वीरेंद्र जैन, वैदेन्द्र कुमार पाटीदार, रायसिंह नरवरिया, रामशरण प्रजापति, सुंदर सिंह कानेश और राजेश व्यास को जगह मिली है। वहीं, विनोद कुमार सिंह, पद्म विलोचन शुक्ला, सुधीर कुमार अग्रवाल, पंकज कुमार पांडेय, अजय पांडेय और डॉ। संजय कुमार अग्रवाल को 2022 की चयन सूची में जगह दी गई है।

महाराष्ट्र: नाबालिग से बदसलूकी करने के आरोप में एक कांस्टेबल सहित पांच गिरफ्तार

चंद्रपुर, 4 जुलाई (एजेंसियाँ)। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उससे बदसलूकी करने के आरोप में एक कांस्टेबल तथा चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चंद्रपुर जिले के पुलिस अधीक्षक रवींद्र सिंह परदेशी ने रविवार को हुई घटना को गंभीरता से लिया और पुलिस की सी-60 इकाई से संबद्ध कांस्टेबल को सोमवार को निर्लांबित कर दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिसकर्मी और उसके दोस्त पार्टी के लिए यहां ममला गए थे। वापस लौटते समय उन्होंने ममला रोड पर एक नाबालिग लड़की और दो जोड़ों को बैठे देखा। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर जोड़ों को धमकाया और लड़की को जबरदस्ती अपने वाहन में बैठाया। इसके बाद उसे जाने दिया। उन्होंने लड़की से कहा कि अगर उसने उनके साथ जाने से इनकार किया तो वे उसके खिलाफ मामला दर्ज करा देंगे।

अतीक- अशरफ की हत्या से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, 14 जुलाई तक टला मामला

नई दिल्ली, 4 जुलाई (एजेंसियाँ)। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या और यूपी में मुठभेड़ों की स्वतंत्र जांच से जुड़ी दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा, फिलहाल हम व्यक्तिगत मुद्दों पर गौर करने के बजाये इस पर ध्यान दे रहे हैं कि क्या इसमें कोई व्यवस्थायत दिक्कत है। साथ ही, इन पर सुनवाई 14 जुलाई तक टाल दी। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ के सामने आई इन दो याचिकाओं में से एक अतीक की बहन आयशा नूरी की तरफ से दाखिल की गई है। इसमें दोनों भाइयों की हिरासत में हत्याओं की जांच के लिए एक



सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग गठित करने की मांग की गई है। वहीं, दूसरी जनहित याचिका राज्य में मुठभेड़ों की स्वतंत्र जांच के लिए वकील विशाल तिवारी की तरफ से दाखिल की गई थी। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान पीठ को बताया कि राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश की है। अदालत स्थिति रिपोर्ट पर गौर कर सकती

है और मामले को सुनवाई के लिए तारीख तय कर सकती है। 30 जून को दायर अपनी स्थिति रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत की गहन, निष्पक्ष और समय पर जांच सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि घटना के बाद गठित न्यायिक आयोग को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और तीन महीने का समय दिया गया है।
मुठभेड़ की जांच के लिए आयोग को दो माह अतिरिक्त समय
प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल व उनके दो सरकारी नगरों की हत्या करने

वाले चार शूटरो के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग को राज्य सरकार ने दो माह का अतिरिक्त समय दिया है। दो सदस्यीय आयोग अपनी रिपोर्ट अगस्त माह के अंतिम हफ्ते में राज्य सरकार का सौंप सकता है। गृह विभाग ने हाल ही में इसका आदेश जारी किया है। प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके दो सरकारी नगरों की माफिया अतीक अहमद के बेटे असद व शूटरो ने ताबड़तोड़ गोलियां और बम बरसाकर हत्या कर दी थी। प्रयागराज पुलिस ने छह मार्च को प्रयागराज में शामिल शूटर अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था।

एसटीएफ ने 13 अप्रैल को झांसी के बड़ागांव क्षेत्र में अतीक के बेटे असद व शूटर मोहम्मद गुलाम को मुठभेड़ में मार गिराया था।
तीनों हत्या के आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई
जिला न्यायालय ने माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। आरोपी लवलेश तिवारी, शनि सिंह और अरुण मौर्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कीअदालत में पेश किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहर्षि ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

मद्रास एचसी ने सेंथिल बालाजी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनाया खंडित फैसला, बड़ी बेंच में होगी सुनवाई



नई दिल्ली, 4 जुलाई (एजेंसियाँ)। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर खंडित फैसला सुनाया है। इस यह याचिका बड़ी बेंच को ट्रांसमर की जाएगी। दरअसल, नकदी के बदले नौकरी मामले में सेंथिल बालाजी ईडी की हिरासत में हैं। नौकरी के बदले नकदी मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी की पत्नी ने मद्रास हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। इस याचिका पर मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट की ओर से इस पर खंडित फैसला सुनाया गया है। अब इस

मोदी मंत्रिमंडल में बदले जा सकते हैं यूपी कोटे के केंद्रीय मंत्री, किनके नाम सबसे आगे

लखनऊ, 4 जुलाई (एजेंसियाँ)। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं इन सब के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी की नजर यूपी पर है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार होता है तो फिर यूपी को तरजीह दी जाएगी।



इन चेहरों को मिल सकता है मौका

उत्तर प्रदेश से महेंद्र नाथ पांडेय, अजय मिश्र टेनी समेत 4 मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है। पांडेय का विभाग भारी उद्योग पर शिवसेना का दावा रहा है। यूपी कोटे से संजीव बालियान का कद बढ़ाया जा सकता है। पांडेय और टेनी का पता कटता है, तो उनकी जगह ब्राह्मणों को साधने के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी या हरीश द्विवेदी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वाजपेयी और द्विवेदी दोनों अभी राष्ट्रीय संगठन में कार्यरत हैं।
जातीय समीकरण पर जोर
बीजेपी में यूपी कोटे से पिछड़े वर्ग के कई चेहर शामिल हैं। माना जा रहा है कि जातीय समीकरण को प्रभावित किए बिना चेहरा बदला

महीने केंद्र सरकार के आदेश के कारण राज्यों को सीधे चावल बेचना बंद कर दिया था। महिलाओं के लिए गैर-लक्जरी बसों में मुफ्त यात्रा की पेशकश करने वाली 'शक्ति' योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है। एपीएल/बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवारों की महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रति माह देने की 'गृह लक्ष्मी' योजना अगस्त में लागू की जाएगी। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा करने वाली गृह ज्योति योजना का लाभ अगस्त से बिलों में दिखना शुरू हो जाएगा। इसी तरह, युवा निधि योजना के तहत बेरोजगार स्नातकों को 3,000 रुपये प्रति माह और 2022-23 में उत्तीर्ण डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये देने की योजना जल्द ही शुरू की जाएगी।

पैसे ने बनाया हैवान

सिर्फ 50 हजार रुपए में पत्नी और 4 साल के मासूम को बेचा, अरेस्ट

कोलकाता, 4 जुलाई (एजेंसियाँ)। पैसों के लिए अपनी पत्नी और चार साल के बच्चे को बेचने का आरोप पति पर लगा है। इस आरोप में फालाकाटा पुलिस ने अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा थाना अंतर्गत उमाचरणपुर इलाके के निवासी नूर हुसैन नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पर अपनी पत्नी और बेटे को बेचने का आरोप है। मालूम हो कि 11 साल पहले थाना इलाके की रहने वाली लवली खातून की शादी फालाकाटा के उमाचरणपुर इलाके के रहने वाले नूर हुसैन से हुई थी। शादी की 11 साल बीत गए। अब उनके परिवार में एक बेटी और दो बेटे हैं। 25 जून को एक बेटी और एक बेटे को घर पर छोड़कर नूर हुसैन अपनी पत्नी लवली और 4 साल के बेटे के

साथ दिल्लीके लिए रवाना हुए। 5 दिन बाद नूर हुसैन एक घर में लौट आया लेकिन लवली और अपने 4 साल के बेटा उसके साथ नहीं थे। जब पत्नी और बेटे के बारे में पूछा गया तो नूर साफ ढंग से यह नहीं बताया कि उसकी पत्नी और बेटे कहाँ हैं। पत्नी और बेटे के लापता होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। इसके बाद घटना की खबर लवली के पिता के घर गयी। पिछले तीन दिनों से नूर हुसैन से उसके परिवार में लवली और उसके बेटे के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। कई बार पूछताछ के बाद भी नूर यह नहीं बताया कि पत्नी और बेटे कहाँ हैं। इसके बाद उन्हें नूर पर शक हो गया। पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच कई सालों से आर्थिक मुद्दों के लेकर विवाद चल रहा था।

स्वतंत्र वाक्ता

बुधवार, 5 जुलाई- 2023

राजनीतिक आंखमिचौली

किसी को कानोकान खबर तक नहीं लगी और महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बार फिर करवट बदल ली। इसी तरह का नाटक महाराष्ट्र में पिछले चार सालों से लगातार चल रहा है। हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि नाटकीय घटनाक्रम थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब चाचा-भतीजे की अटूट जोड़ी के भतीजे ने चाचा को ही गन्धा दे दिया और कुछ ही पलों में राजनीति का ककरहा तक बदल दिया। गुरुपूर्णिमा यानी रविवार को एनसीपी के शीर्ष नेताओं में गिने जाने वाले विधायकों व सांसदों ने अपने ही गुरु शरद पवार को अंधेरे में रख कर एकनाथ शिंदे सरकार को समर्थन दे दिया। इसके साथ ही भतीजा अजित पवार उपमुख्यमंत्री बन गए और राकांपा के आठ विधायक मंत्री पद हासिल करने में कामयाब हो गए। जाहिर है यह भाजपा के लिए जहां बड़ी जीत मानी जा रही है तो वहीं शरद पवार के लिए बकाा का सीएम एकनाथ शिंदे ने खुशी जाहिर की कि उनकी सरकार को और ताकत मिल गई है तो बड़ी संख्या में लोग इसे भाजपा की बदले की कार्रवाई मान रहे हैं। सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव भाजपा और शिवसेना ने साथ मिल कर लड़ा था। भाजपा सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरी थी। लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो शिवसेना सुप्रिमो सीएम पद को लेकर अड गए। बात नहीं बनी तो शिवसेना ने उसके साथ सरकार बनाने से ही इंकार कर दिया था। उस आड़े वक्त में अजित पवार भाजपा के साथ खड़े हो गए थे। तब देवेन्द्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। लेकिन विधायकों ने अजित पवार को गन्धा दे दिया और वह सरकार मात्र तीन दिन में ही गिर गई थी। फिर शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के गठबंधन से महाविकास अघाड़ी नाम से सरकार बनाई। लेकिन करीब दो साल बाद उद्व्व ठाकुर के बेहद करीबी रहे एकनाथ शिंदे ने बग़ावत कर दी और शिवसेना के कई विधायकों को लेकर भाजपा से हाथ मिला लिया था। इसके बाद उद्व्व ठाकुरे सरकार समय से पहले ही निपट गई। अब लगभग वही पट्टाक्रम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दोहराया गया है। इस बार अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के रास्ते पर चलते हुए सरकार में शामिल हो गए हैं। उनके जगते से निस्संदेह राकांपा को बड़ा झटका लगा है, लेकिन कितना यह तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। बहरहाल, पार्टी के ज्यादातर बड़े और शरद पवार के भरोसेमंद नेताओं ने बग़ावत की है। यही नहीं बागी नेता अब पार्टी के नाम और निशान पर भी अपना दावा ठोकने लगे हैं। मंगलवार को पार्टी कार्यालय पर भी बग़ावती गुट ने काफी झूमाझटकी की है। एनसीपी ने अजित पवार और उनके साथ गए नेताओं के कदम को गैरकानूनी बताया है। इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पार्टी नियमों के अनुसार न तो अजित पवार को विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार था और न पार्टी आलाक़मान की इजाजत के बग़ैर उन्हें इस तरह सरकार में शामिल होने का। इसे अवैधता के चुनौती देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी तरह शिवसेना ने भी एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों को कानूनी चुनौती दी थी, मगर उसका कोई फल उसे नहीं मिला। इससे जाहिर होता है कि राकांपा की भी इसमें कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। अगले साल वहां विधानसभा के चुनाव हैं और तब तक अख़्तलाती कार्रवाई शायद ही पूरी हो पाए। कानूनन चुन कर आए प्रतिनिधियों को सरकार बनाने के समीकरण तय करने का लोकांत्रिक अधिकार है। लेकिन जिस तरह पिछले चार सालों में सैद्धांतिक मूल्यों को धता बलते हुए सत्ता की घुड़दौड़ चल रही है, उससे अख़िरकार उगे तो मतदाता ही जा रहे हैं। मतदाता तो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव न केवल उनके व्य्विक्तत्व को देख कर बल्कि उनकी पार्टी के सिद्धांतों को भी तरज़ीह देकर करते हैं। शिवसेना को छोड़ कर अलग हुए नेताओं को मतदाताओं ने शिवसेना के सिद्धांतों के आधार पर चुना था। लेकिन जब वे अलग हुए तो जाहिर है उन्होंने अपने मतदाताओं की भावनाओं की कद्र नहीं की। इसी तरह राकांपा के विधायकों ने भी पार्टी से बग़ावत कर अपने मतदाताओं को ही उगा है। हर राजनीतिक दल और विधायक चुनाव इसीलिए लड़ता है कि सत्ता में आए, मगर सिद्धांतों और नियम-कायदों को ताक पर रख कर केवल सत्तासुख के लिए समझौता कर लेने से लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या होगा ?

बंद दरवाजा

पुषेष् कुमार पुष्प

वर्षों से मोहल्ले में रह रहे जितने बाबू का अचाक्क से अमीरों की श्रेणी में आ जाना , लोगों की समझ से परे थी । एक समय था जब वे फटेहाली का जीवन जीने को मजबूर थे । उस समय तो वे लोगों से हिल - मिलकर रहते थे , लेकिन अब तो उनके रहन - सहन के तौर - तरीके बदल गये थे। अब तो वे लोगों से बात करना तो दूर उन्हें नजर उठाकर देखना भी पसंद नहीं करते। उनकी शान और शौकत देखते ही बनती थी। मोहल्ले के लोगों के लिए उनके घर के दरवाजे सदैव ही बंद रहते थे। लोगों की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर जितने बाबू ने ऐसा कौन - सा धंधा शुरू कर दिया कि रातों - रात अमीर बन गये । आज उनके बेटे अमित का जन्मदिन था । उनके घर के आगे शहर के जाने - माने लोग और नेता - मंत्रियों की गाड़ियां लगी थी । उन्होंने उसके जन्मदिन पर केवल बड़े लोगों को ही आमंत्रित किया था । लेकिन अमित के ज़िद के कारण मोहल्ले के बच्चों को अकेले ही आना का निमंत्रण मिला था । अमित के जन्मदिन समारोह में मेरी बच्ची भी गयी थी । वह घर आते ही कहने लगी - पापा ! अगर मेरा भी जन्मदिन मनाइये न । जैसे अमित का जन्मदिन मनाया गया । उसके जन्मदिन पर खाने को क्या नहीं था ? उसे कितना उपहार मिला । मुझे भी उतना ही उपहार मिलेगा । आप क्यों नहीं मनाते मेरा जन्मदिन और लोगों को क्यों नहीं बुलाते ? मैं अपनी बच्ची की बात सुनकर सोचने लगा - एक छोटा - सा लेखक अपनी बेटी का जन्मदिन कहां से मनायेगा और यदि मनाऊंगा भी तो क्या मुझ जैसे छोटे लेखक की बेटी को उतना उपहार मिल पायेगा ? मैं बिना कुछ बोले ही अपनी बेटी को एकटक निहारने लगा । तभी मेरी पत्नी का प्रचवन शुरू हो गया - मेरी तो किस्मत ही फूट गयी थी , जो आपसे शदी हुई । आपसे तो अच्छा एक सच्ची

ओबामा पहले अमेरिका के गिरेबान में झांक कर देखें !



श्रवण गर्ग

बचना चाहिए । अमेरिका के किसी अन्य तत्कालीन अथवा पूर्व राष्ट्रपति ने इस संवेदनशील मुद्दे पर वैसा हस्तक्षेप नहीं किया जैसा ‘फ्रेंड ओबामा’ 2014 के बाद से कर रहे हैं। वे भारत की यात्रा पर आते हैं तब भी नहीं चूकते और अपने देश में बैठे-बैठे भी उन्हें चैन नहीं मिलता ।

भारत का हिंदू-मुसलिम मामला उतना गंभीर नहीं है जितना ओबामा बनना चाहते हैं या अमेरिका में डॉनल्ड ट्रम्प और उनकी रिपब्लिकन पार्टी ने वहाँ के गोर-सवर्णों और तमाम अश्वेतों ,जिनमें कि मुसलिम भी शामिल हैं, के बीच बना रखा है। ट्रम्प समर्थक सवर्ण तो अब अपनी ही संसद पर हमले भी कर रहे हैं और ओबामा उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं ! ओबामा जानते होंगे कि जितनी आबादी (24 करोड़) उनके देश में गिरे सवर्णों की है लगभग उतने भारत में मुसलमान हैं। भारत की हिन्दू-मुसलिम समस्या अमेरिका की तरह का कोई स्थायी विभाजन नहीं है।

एक कट्टर हिंदूवादी पार्टी के पिछले नौ सालों से सत्ता में होने के बावजूद ऐसा संभव नहीं हो पाया है। मौजूदा सरकार को दिल्ली से बिदाई के साथ सारा हिंदू-मुस्लिम तूफ़ान शांत भी हो जाएगा। यह काम देश की जनता बिना ओबामा की मदद के संपन्न कर लेगी। उसे पता है कि 2014 के पहले यह समस्या इतनी चिंताजनक कभी नहीं रही। गुजरात के 2002 के दुर्भाग्यपूर्ण एपिसोड को छोड़ दें तो अटलजी जी के नेतृत्व

वाली एनडीए की (1999 से 2004) हुकूमत के दौरान भारत के अल्पसंख्यक अपने आप को कांग्रेस के ज़माने से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते थे। ओबामा को समझाया जाना चाहिए कि मोदी-शाह-योगी भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा नहीं हैं। भारत की मूल आत्मा सर्वधर्म समभाव की है और यही राष्ट्र का स्थायी चरित्र है। ऐसा नहीं होता तो सवा दो सौ सालों (1526-1761) में मुग़ल शासक भारत की एक इस्लामी राष्ट्र, अंग्रेज लगभग सौ सालों (1858-1947) में ईसाई राष्ट्र और संघ पिछले सौ सालों (1925-2023) में हिंदू राष्ट्र बनाने में कामयाब हो जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना की कल्पना हिंदू बहुसंख्यकवाद की ताकत के बल पर अपने आप की सत्ता में बनाये रखने का एक साधन मात्र है।संघ का साध्य भिन्न है। ओबामा अगर हिंदू राष्ट्रवाद के कारण भारत के टूटने के भय से परेशान हैं तो उन्हें सबसे पहले 2024 के अमेरिकी चुनावों में ट्रम्प की सत्ता में वापसी को रोककर दिखाना चाहिए ।

ओबामा जानते हैं कि 2017 में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के तत्काल बाद किस तरह ट्रम्प ने कुछ मुसलिम मुल्कों के नागरिकों के अमेरिका प्रवेश पर रोक लगाई थी। ट्रम्प फिर से सत्ता में आ गए तो मुसलिमों ही नहीं सभी ग़ैर-सवर्णों का अमेरिका में जीना दूभर कर देंगे।

एक ऐसे समय जब मोदी अपनी पहली राजकीय यात्रा पर उनके देश में थे और उनकी ही पार्टी के नेता-राष्ट्रपति और किसी समय उनके ही उपराष्ट्रपति रह चुके बाइडन के साथ चर्चा में भारत की लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता ज़ाहिर कर रहे थे, ओबामा की टेलीविजन-साक्षात्कार टिप्पणी भारतीय प्रधानमंत्री के साथ एक अन्यायपूर्ण कृत्य था। ओबामा ने बजाय ऐसा करने कि वे बाइडन के साथ हुई संयुक्त प्रेस कॉफ़्रेस में लोकतंत्र और धार्मिक

यूसीसी के नाम पर विपक्ष में सैंधमारी हो सकती है

देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर माहौल बनने लगा है। जिस विवाद पर पहले सिर्फ मंथन रहता था, अब चर्चा काफी आगे बढ़ चुकी है। माना जा रहा है कि इस मॉनसून सत्र में मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बिल ला सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये देश की सियासत में एक बड़ा नाटकीय मोड़ साबित होने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी को यूसीसी पर पर्याप्त समर्थन मिल सकता है? अब इसका सबसे आसान जवाब तो लोकसभा और राज्यसभा के नंबर गेम को जान दिया जा सकता है। लेकिन पहले कई दलों की सियासी विचारधारा को समझना भी जरूरी है। ये विचारधारा ही वो फैक्टर है जो बीजेपी को यूसीसी पर या तो बड़ा झटका दे सकती है या फिर एक बड़ी राहत। ऐसे में तमाम पार्टियों का यूसीसी पर क्या रुख है, ये जानना पड़ेगा।

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कन्स्यूज कही जा सकती है। इसका कारण ये है कि पार्टी के अंदर ही कई ऐसे गुट हैं जो यूसीसी का समर्थन करते हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी सामने आए हैं जो पूरी तरह इस कानून के विरोध में हैं। यानी कि पार्टी सामने से आकर तो जरूर खिलाफ में बयान दे रही है, लेकिन कुछ नेता अंदरखाने इस बिल का स्वागत कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूसीसी को अपनी तरफ से पूरा समर्थन दे दिया है। साफ कहा गया है कि वे इस पथल को पसंद कर रहे हैं। अब सेफ खेलते हुए अगले ही बयान में उनकी तरफ से मोदी सरकार की टाईमिंग पर जरूर सवाल उठा दिया गया है। दूसरी तरफ बात जब कांग्रेस महासचिव जययाम रमेश की आती है, उन्होंने दो टूक कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ना जरूरत है ना ही कोई वर्तमान में इसकी इच्छा रखता है। वहीं अमेिका मनु अपने कारण हैं। एक तरफ वे मानकर चल रहे हैं कि यूसीसी के जरिए एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा सकता है, वहीं ये भी कहना है कि वो काम संसद में होना चाहिए, लॉ कमिशन का हस्तक्षेप होना ठीक नहीं। इसी संकेत में आरजेडी, टीएमसी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है। अब तमाम पार्टियों की विचारधारा की बात तो हो गई है। बात अगर देश के प्रथम प्रधनमंत्री जवाहर लाल नेहरू की जाए, तो पता चलता है कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिद्धांत के खिलाफ

नहीं थे। एक समय देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीम राव आंबेडकर के उस विचार से नेहरू भी सहमत थे जहां यूसीसी लाने की बात कही गई थी। लेकिन उस समय क्योंकि संविधान सभा यूसीसी के लिए तैयार नहीं थी, ऐसे में भारी विरोध हुआ और यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बनने से रह गया।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय विपक्षी एकता में व्यस्त चल रहे हैं। लेकिन बात जब यूसीसी की आती है, उनकी पार्टी ने कभी भी इसका खुले तौर पर विरोध नहीं किया है। खुद नीतीश कुमार ने एक बयान में कहा था कि यूसीसी को तो लोगों के लिए रीफॉर्म के तौर पर देखा जाना चाहिए, उन्होंने सिर्फ इतनी अपील की थी कि इसे जल्दबाजी में लागू ना किया जाए। अब उसी तर्ज पर जेडीयू नेता केशी त्यागी ने कह दिया है कि उनकी पार्टी यूसीसी का विरोध नहीं करती है, बस एक मांग है कि सभी को साथ लेकर चला जाए। यानी अगर संसद में इस मुद्दे पर उचित मंथन हो जाए, सरकार अपने तर्क समझाने में कामयाब हो जाए, उस स्थिति में शायद जेडीयू भी विपक्ष को कोई बड़ा सरप्राइज दे सकती है। अब जेडीयू को लेकर तो अभी संशय की स्थिति है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम आदमी पार्टी मोदी सरकार को सपोर्ट कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी ने खुद ही साफ कर दिया है कि वो इस विचार के खिलाफ नहीं हैं। आप नेता संदीप पाठक ने कह दिया है कि पार्टी सैद्धांतिक तौर पर यूसीसी का समर्थन करती है, मानती है कि इसे लागू होना चाहिए। कुछ दूसरे दल की तरफ आप ने भी सभी के साथ चर्चा की बात जरूर कर दी है। उद्व्व गुट भी इस समय बीजेपी से खफा चल रहा है, लेकिन यूसीसी पर समर्थन देने की बात कर गया है। ये नहीं भूलना चाहिए कि बालासाहेब ठाकरे यूनिफॉर्म सिविल कोड के एक बड़े पक्षधर थे।

लेफ्ट पार्टियों की बात करें तो उनके विरोध के अपने कारण हैं। एक तरफ वे मानकर चल रहे हैं कि यूसीसी के जरिए एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा सकता है, वहीं ये भी कहना है कि वो काम संसद में होना चाहिए, लॉ कमिशन का हस्तक्षेप होना ठीक नहीं। इसी संकेत में आरजेडी, टीएमसी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है। अब तमाम पार्टियों की विचारधारा की बात तो हो गई है। बात अगर देश के प्रथम प्रधनमंत्री जवाहर लाल नेहरू की जाए, तो पता चलता है कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिद्धांत के खिलाफ

300 से ज्यादा का आंकड़ा साथ है। ऐसे में काफी आसानी से यूसीसी बिल को पारित करवाया जा सकता है। लेकिन सारा खेल राज्यसभा में जाकर फंसता है जहां पर बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है, उसके सहयोगी दलों को भी मिला दिया जाए तो भी जादुई आंकड़ा नहीं पहुंचता। इसी वजह से राज्यसभा में बीजेपी की जुगाड़ू पॉलिटिक्स की असली परीक्षा होने जा रही है। असल में राज्यसभा में इस समय कुल सदस्यों की संख्या 237 चल रही है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आठ सीटें रिक्त पड़ी हैं। इसी वजह से बहुमत का आंकड़ा भी 119 पर चल रहा है, यानी कि अगर कोई भी बिल पारित करवाना है, तो इतना समर्थन तो जुटाना ही पड़ेगा। अब यूसीसी पर बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 108 सदस्यों का समर्थन मिल सकता है। अब कुछ दिन पहले की बात करते तो ये आंकड़ा 109 रहता क्योंकि बीजेपी के पास राज्यसभा में तब 92 सदस्य थे। लेकिन हाल ही में क्योंकि सांसद हट्टार दुबे का निधन हो गया, ऐसे में एक सीट कम हो गई।

अब सिंपल गणित ये कहती है कि बीजेपी को किसी भी तरह 11 और सांसदों का समर्थन चाहिए, उसी स्थिति में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। लेकिन ये समर्थन आएगा कहाँ से? इस समय आम आदमी पार्टी और उद्व्व गुट ने कह दिया है कि वो यूसीसी का समर्थन करते हैं। ऐसे में अगर एएपी के 10 सांसद बीजेपी को सपोर्ट कर जाते हैं और उद्व्व की शिवसेना के भी 3 सांसद साथ आ जाते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बन जाएगा। इसी तरह अगर आम आदमी पार्टी और उद्व्व गुट के बजाय बीजेपी को नवीन पटनायक की बीजेडी और रेड्डी की YSR पार्टी का सपोर्ट मिल जाता है, तब भी यूसीसी आसानी से हकीकत बन जाएगा। इस समय राज्यसभा में दोनों YSR कांग्रेस और बीजेडी के पास 9-9 सांसद हैं, यानी कि कुल आंकड़ा 18 पहुंच रहा है। बीजेपी की बहुमत के लिए सिर्फ 11 का आंकड़ा चाहिए, ऐसे में ये पार्टी के लिए सबसे अनुकूल स्थिति साबित हो सकती है। बीजेपी इन दो पार्टियों का समर्थन इसलिए भी चाहती है क्योंकि कई बड़े फैसलों के दौरान इन दलों ने विपक्षी एकता से इतर समर्थन दिया है। वैसे कुछ ऐसे भी समीकरण बन सकते हैं, जिनकी उम्मीद कम है, लेकिन उन्हें पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। असल में जेडीयू पूरी तरह यूसीसी के खिलाफ नहीं है, वो बस चर्चा चाहती है।

फ्रांस में इस्लामिक चरमपंथी फैला रहे हैं उन्माद !



मनोज कुमार अग्रवाल

एक किशोर की पुलिस गोली से हुई मौत को लेकर फ्रांस में जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। फ्रांस में हो रही हिंसक वारदातों आगजनी पथराव में अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाले फ्रांसीसी शहर बर्दगॉ हो रहे हैं फ्रांस के मॉर्सिले शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की भी उन्मादी तत्वों ने आग के हवाले कर दिया।पिछले कुछ दिनों से यहां आक्रोश और अराजकता का नांग नाच जारी है। दरअसल फ्रांस में पिछले लम्बे समय से नस्लीय भेदभाव के आरोप लगाए जाते रहे हैं मौजूदा मामला फ्रांस में निम्न मध्यम अफ्रीकी व नाइजीरिया मूल के लोगों के साथ पिछले कुछ सालों से चल रहे कथित नस्ली भेदभाव से उपजे संतोष का नतीजा भी माना जा रहा है।वहीं कुछ लोग इसे इस्लामिक चरमपंथियों द्वारा फ्रांस में कट्टरता व अराजकता का फैलाव करार दे रहे हैं। फ्रांस में एक 17 साल के मुस्लिम लड़के की पुलिस की गोलीबारी में मौत के बाद लगातार हिंसा जारी है। हिंसा और आगजनी की घटनाओं में अब तक दो हज़ार गाड़ियां जलाई जा चुकी हैं. और 492 घरों को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि फ्रांसीसी पुलिस ने देशभर के अलग-अलग इलाकों से अब तक करीब तेरह सौ लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक की है। इसमें शामिल होने के बाद फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने कहा कि आपातकालीन कैबिनेट बैठक का उद्देश्य व्यवस्था बहाल करने के लिए सभी विकल्पों की समीक्षा करना था। उन्होंने यह भी बताया कि इसमें फ्रांस में आपातकाल की परिस्थितियों पर चर्चा भी शामिल थी। फ्रांस की सरकार ने कहा है कि पुलिस द्वारा किशोर की हत्या के बाद चौथी रात हुए दंगों में कई हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज रिपोर्टर्स के अनुसार जर्मन अधिकारियों का कहना है कि फ्रांस में अशांति के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जर्मनी की राजकीय यात्रा स्थगित कर दी है. सरकार ने कहा कि पिछली रातों की तुलना में हिंसा कम हुई है, लेकिन आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने अभी भी रात भर में देश भर में 1,311 गिरफ्तारियों की सूचना दी है। शनिवार सुबह जारी किए गए मंत्रालय के आंकड़ों में कहा गया है कि रात भर में 1,350 वाहनों और 234 इमारतों को आग लगा दी गई थी और सार्वजनिक स्थानों पर आग लगाने की 2,560 घटनाएं हुई थीं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि 79 पुलिस घायल हुए हैं. फ्रांस सरकार द्वारा 45,000 अधिकारियों को तैनात करने के बावजूद झड़पें जारी हैं।आप को बता दें कि 27 जून को फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस ने एक किशोर को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आरोप में गोली मार दी, जिसमें नाबालिग की मौत हो गई। इस घटना के बाद फ्रांस में हिंसा भड़क उठी और अब विकराल रूप ले चुका है।इस गोलीबारी की घटना पर पुलिस ने बताया कि नाबालिग तेज रफ्तार से एक रेंटल कार को चला रहा था। पुलिस ने उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने कई बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने गोली चलाई।घटना के बाद, लोगों के मन में पुलिस के खिलाफ नफरत की धारणा बन गई। लोग ऐसा सोचने लगे कि पुलिस किसी को भी गोली मार सकती है और लोग इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। सड़क पर आने के बाद लोगों ने जमकर उत्पात मचाया है। कई सरकारी वाहन फूंक दिए गए। पुलिस पर पथराव किए गए। साथ ही कई बिल्डिंगों में आगजनी की घटना भी सामने आई है। पुलिसकर्मों द्वारा किशोर की गोली मारकर हत्या करने की निंदा हो रही है। सरकार ने भी अपने बयान में सुरक्षाबलों की ही आलोचना की है घटना के जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को जेल भेज दिया गया है । राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि किशोर की हत्या अस्वीकार्य और अक्षय्य है। इस हत्याकांड को किसी भी तरह से न्यायोचित करार नहीं दिया जा सकता। बता दें कि फ्रांस में इस घटना से पुलिस नियमों में सुधार की मांग उठने लगी है। खासकर जातीय अल्पसंख्यकों से डील करने के मामले में पुलिस के व्यवहार की आलोचना शुरू हो गई है। बीते साल फ्रांस में पुलिस की कार्रवाई में 13 लोगों की मौत हुई थी। जानकारों के अनुसार नाहेल टेकअलवे डिलीरीरी झाइवर के रूप में काम करता था और अपनी मां का इकलौता सहाया था। उसे रबी खेलना पसंद था और वह पिछले तीन वर्षों से पाइरेट्स ऑफ नैट्नेट्स रबी क्लब का सक्रिय सदस्य था। नाहेल की मां मौनिया का दावा है कि अलजीरियाई मूल के होने के नाते पुलिस ने उसका चेहरा देख उस गोली मार दी मृत लड़के की मां ने बताया है कि पढ़ने-लिखने में मन नहीं लगने के कारण उसकी दिलचस्पी इलेक्ट्रिशियन बनने में थी।

जो भी ओ नाहेल की मौत से भड़का विशेष रूप से एक समुदाय विशेष और उनके समर्थक फ्रांस में हिंसा आगजनी और पथराव पर उतारू है और कानून व्यवस्था धराशाय हो गई है। बताया जाता है कि फ्रांस में मुस्लिम चरमपंथी इस घटना से उपजे आक्रोश की आड़ में अराजकता पर उतारू हैं पिछले 25 सालों में फ्रांस में मुस्लिमों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसके अलावा, पिछले कुछ दशकों में फ्रांस में अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया और उप-सहारा अफ्रीका से मुस्लिम प्रवासियों की लगातार आमद देखी गई है।





दौरान इन स्थानों के दर्शन होते हैं।
अमरनाथ यात्रा का महत्व
 कहा जाता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन से हजार गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बता दें अमरनाथ में शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से टपकती पानी की बूंदों से होती है। कहते हैं कि यह शिवलिंग चंद्रमा की रोशनी के चक्र के साथ घटता और बढ़ता है। बर्फ से बने शिवलिंग के कारण ही इसे 'बाबा बर्फानी' कहते हैं। गौरिलंब है कि इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक कर सकते हैं।

क और भद्रा का साया भी
प्राति योग रहेगा, जिसे बहुत ही शुभ नक्षत्र
का साया भी रहने वाला है। भद्रा सुबह
जा कर सकेंगे। क्योंकि ज्योतिष के अनुसार
दिन पंचक दोपहर 01:38 मिनट से शुरू हो

शादी में अंगूठी से क्यों भरी जाती है मांग



को भी
न रहे।
देने की
क यह
जिनको
श्रीराष्ट्र
तरापथ
क्षे।
मर्यादा
नों की
न पुण्य
तरापथ
र होता
क्यों के
कमात्र
र लिए
शतशत

का सांस्कृतिक महत्व है। आपन विवाह में ल
को अंगुठी से दुल्हन की मांग में सिन्दूर भरते
देखा होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस
का मनुष्य के जीवन में बहुत खास महत्व होता
हिन्दू धर्म में अंगुठी से सिन्दूर भरना सौभाग्य
बढ़ाने वाला माना जाता है। अंगुठी से सिन्दूर ल
के कई प्रतीकात्मक अर्थ हैं। अंगुठी पति का अपनी
के प्रति प्यार और प्रतिक्रिया को दर्शाती है। भो
निवासी ज्योतिषी और वास्तु सलाहकार पंडित ह
कुमार शर्मा बता रहे हैं इस प्रथा के कारणों और इ
महत्व के बारे में।

अंगुठी से मांग में सिंदूर लगाने का महत्व
दुल्ह द्वारा दुल्हन की मांग में सिन्दूर लगाने
प्रतीकात्मक अर्थ तो है ही साथ ही अंगुठी से स
भरने के कई अन्य लाभ भी होते हैं। ज्योतिष श
मानता है कि सिन्दूर का लाल रंग जीवन से
शक्तियों को दूर रखता है। जबकि अंगुठी पलं
स्वास्थ्य की रक्षा करती है। हिन्दू धर्म में अंगुठ
सिंदूर लगाने की प्रथा कई सदियों पुरानी है।



आज भी हिंदू संस्कृतियों में व्यापक रूप से प्रचलित है। यह प्यार, प्रतिबद्धता और सुरक्षा का प्रतीक है और यह विवाहित महिलाओं के लिए अपनी पहचान दिखाने का एक तरीका है।

दाम्पत्य के दौरान जब अंगूठी से मांग भरी जाती है, तो यह पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम को दिखाती है। अंगूठी को दाम्पत्य जीवन के अटूट प्रेम की निशानी माना जाता है। अंगूठी से सिन्दूर लगाकर पति-पत्नी के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को दिखाता है कि वह उससे हमेशा प्यार करेगा और किसी भी परिस्थिति में पत्नी का साथ नहीं छोड़ेगा।

शुभता और सौभाग्य का प्रतीक है अंगूठी से

19 साल बाद सावन में मलमास का बना संयोग

4 पलियां या पति सभी का अपना एक होता है। सिर्फ जोधे आपका अंतिम समय है। पहली पत्नी या अपना शरीर। आप की प्रेम कर लें, आपका खयाल रख लें, य य थे आपका साथ है। आपकी दूसरी पत्नी आपका भाग्य है। भी भाग्य साथ लेकर आपके साथ कभी नहीं र हट्ट जाता है। फिर पा पति आपके रिश्ते- भाई-बहन जैसे सगे तत्व तक ही आपके तक आप जीवित हैं। वे भी आपका साथ पा पति आपके कर्म में जीवित में जो भी यह मारने के बाद साथ जाते हैं। इन वाशर पर आपके का निर्धारण होता है ही आपकी स्वर्ग न द्वा द्वि दिखाते हैं।

कारण इस महीने में मांगलिक कार्यों की मनाही होती है।

पूजा का मिलेगा शुभ फल

उन्होंने बताया कि मलमास भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस अवधि में विष्णु भगवान की उपासना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं सावन मास बाबा भोलेनाथ को समर्पित होता है, इसलिए जो भक्त उक्त निमित्त पूजा अर्चना करता है, उससे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है।

कैसे हुई मलमास की उत्पत्ति

योगेश कुकरोती के अनुसार, मलमास की उत्पत्ति हिरण्यकश्यप के कारण की गई थी। दरअसल, जब हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की थी तो उसने वरदान मांगा था कि मुझे कोई न दिन में मार सके, न रात में मार सके, न घर में मार सके, न बाहर मार सके और न कोई मुझे वर्ष के बारह माह में मार सके। हिरण्यकश्यप के वध की कथा तो आपने सुनी ही होगी कि किस तरह नरसिंह भगवान आधे मानव और आधे शेर के वज्रवतार में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया। उसके वरदान के अनुसार ही वर्ष 12 माह की जगह 13 माह किए गए। यह रीति तीन साल बाद आता है। इसे आप लीप पर की तरह ही मान सकते हैं।



बगावत करके सबसे युवा सीएम बने थे शरद पवार

मुंबई, 4 जुलाई (एक्सक्लूसिव डेस्क)। महाराष्ट्र में रविवार को एक राजनीतिक भूकंप आया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने बगावत कर दी और 8 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अजित ने एनसीपी पर भी दावा करके चाचा की वही छुट्टी पिलाई है, जो 83 वर्षीय शरद पवार अपने पॉलिटिकल करियर में कई बार कर चुके हैं। आज तीन किस्सों से जानेंगे कि कैसे शरद पवार ने बगावत की और राजनीति में सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ते गए।

1978 में जब बगावत करके महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने

साल 1977 की बात है। आपातकाल के बाद कांग्रेस दो गुटों इंदिरा की कांग्रेस (आई) और रेड्डी की कांग्रेस (यू) में बंट गई। शरद पवार कांग्रेस (यू) में शामिल हो गए। 1978 में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए तो दोनों कांग्रेस अलग-अलग लड़ीं। जनता पार्टी कुल 288 में से 99 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत से पीछे रह गई। इंदिरा की कांग्रेस को 62 और रेड्डी कांग्रेस को 69 सीटें मिलीं। चुनाव के

कांग्रेस ने निकाला तो एनसीपी बनाई, अजित ने वही दांव पलट दिया

बाद दोनों कांग्रेस ने साथ मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल बने और नासिकराव तिरपुडे डिप्टी सीएम बने। सरकार के बनने के साथ ही कई नेताओं में असहमति भी बढ़ने लगी।

जुलाई 1978 में महाराष्ट्र के सीएम वसंतदादा पाटिल ने शरद पवार को घर पर खाने के लिए बुलाया। दरअसल, सीएम अपने युवा उद्योग मंत्री के साथ कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। उसम भरी दोपहरी में शरद पवार सीएम के घर पहुंचे। उन्होंने उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा की और खाना खाया। जब घर से चलने की बात हुई तो उन्होंने सीएम पाटिल के सामने हाथ जोड़कर कहा- दादा अब मैं चलता हूं, कोई भूल चूक हो तो माफ करना। तब सीएम वसंत दादा कुछ समझे नहीं, लेकिन शाम होते होते राज्य सरकार में बगावत की बात सामने आने लगी। सरकार बने हुए साढ़े चार महीने ही हुए थे कि शरद पवार ने 40 विधायकों के साथ बगावत कर दी। इससे गठबंधन सरकार गिर गई। शरद पवार की महत्वाकांक्षा सीएम बनने की थी।

उन्होंने अपनी 'सोशलिस्ट कांग्रेस' की ओर से जनता दल के साथ सरकार बनाने की पहल की। 18 जुलाई 1978 में शरद पवार 38 साल की उम्र में 'प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी' यानी प्रलोद की सरकार बनने के साथ महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी। जनता पार्टी में फूट पड़ गई। इंदिरा गांधी की सिफारिश पर डेढ़ साल बाद ही महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और पवार की पहली सरकार को बर्खास्त कर दिया गया।

राजीव गांधी के करीब आए और दोबारा सीएम बने
1980 में महाराष्ट्र सरकार के बर्खास्त होने के बाद पवार लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहे। हालांकि, इस दौरान

अपनी 'सोशलिस्ट कांग्रेस' की ओर से जनता दल के साथ सरकार बनाने की पहल की। 18 जुलाई 1978 में शरद पवार 38 साल की उम्र में 'प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी' यानी प्रलोद की सरकार बनने के साथ महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी। जनता पार्टी में फूट पड़ गई। इंदिरा गांधी की सिफारिश पर डेढ़ साल बाद ही महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और पवार की पहली सरकार को बर्खास्त कर दिया गया।

राजीव गांधी के करीब आए और दोबारा सीएम बने
1980 में महाराष्ट्र सरकार के बर्खास्त होने के बाद पवार लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहे। हालांकि, इस दौरान



महाराष्ट्र समेत देश में कई राजनीतिक बदलाव हुए। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन बढ़ा और 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। साल 1984 में राजीव गांधी पीएम बने और कांग्रेस की कमान संभाली। यह वह दौर था जब कांग्रेस में युवा पीढ़ी को बढ़ावा दिया जा रहा था। पवार ने अपनी राजनीतिक आत्मकथा में लिखा है- 'राजीव गांधी ने कांग्रेस में वापस आने और साथ काम करने की इच्छा जताई थी।' हालांकि, महाराष्ट्र और कांग्रेस के कुछ नेता पवार की वापसी के खिलाफ थे। इसी दौरान राजीव गांधी की आंंधी के सामने पवार बरामती से लोकसभा सांसद बने। साल 1986 में राजीव गांधी के कहने पर वह कांग्रेस में लौट आए और महाराष्ट्र में फिर से सक्रिय हो गए। यह वह दौर था जब महाराष्ट्र में शिवसेना का प्रभाव बढ़

रहा था। ऐसे में कांग्रेस को राज्य में शरद के रूप में एक युवा नेतृत्व की जरूरत भी थी। 1988 में राजीव गांधी ने शंकरराव चव्हाण को अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया और शरद पवार दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। **1999 में सोनिया गांधी के विरोध से अस्तित्व में आई एनसीपी**
साल 1995 आते-आते गठबंधनों का दौर शुरू होता है। महाराष्ट्र में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन मिलकर सरकार बनाते हैं। ऐसे में पवार एक बार फिर से केंद्र की राजनीति में सक्रिय होते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं। अप्रैल 1996 में देश में लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार बनाने लायक उसके पास संख्या नहीं थी। इस लोकसभा चुनाव में ज्यादातर सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के पास चली गईं। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 129 सीटों पर क्षेत्रीय दलों का कब्जा हो गया। यहीं से क्षेत्रीय दलों के दबदबे की राजनीति शुरू हुई। पवार कांग्रेस की ओर से

लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। कहा गया कि गठबंधन के इस दौर में पवार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की दौड़ में करीब पहुंचे थे। कांग्रेस बहुमत में नहीं थी, लेकिन उसके समर्थन से सरकारें बन रही थीं। हालांकि, सोनिया गांधी के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। इसकी वजह उस वक्त के कई सीनियर कांग्रेस नेता थे। इसी बीच सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में आने का फैसला किया और फिर कांग्रेस के अंदर का गणित भी बदल गया। कांग्रेस के अंदर मौजूद एक बड़े वर्ग की राय थी कि सोनिया को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ऐसे में पवार को लगा कि अब उनका पीएम बनने का सपना पूरा होना मुश्किल है। ऐसे में 1999 में शरद पवार ने सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया और पीएम संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बनाई। कांग्रेस में पवार की यह दूसरी बगावत थी।

अब 2 जुलाई 2023 को अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार को उन्हीं की पॉलिटिकल भाषा में जवाब दिया है। अब देखना ये है कि क्या इस बगावत से अजित पवार का पॉलिटिकल करियर भी मजबूत होगा।

नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में की ग्रामीण की हत्या

कांकिर, 4 जुलाई (एजेंसियां)। कोयलीबेड़ा थाना इलाके के जूंगड़ा गांव के एक व्यक्ति की हत्या की जिम्मेदारी नक्सलियों ने ली। 26 जून को जूंगड़ा निवासी सनकू राम गोटा की हत्या कर नक्सलियों ने शव फेंक दिया था। पुलिस अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही थी। सप्ताह भर बाद नक्सलियों ने कोयलीबेड़ा-आलपरस मार्ग में बैनर पोस्टर लगाकर हत्या की जिम्मेदारी ली है। नक्सलियों ने मुखबिरी की शक में हत्या करना स्वीकार किया है। बैनर में लिखा है कि पार्टी का समाचार कोयलीबेड़ा थाने में देने के कारण मौत का घाट उतारा गया है। गौरतलब हो कि नक्सली जब किसी व्यक्ति को मुखबिरी के शव में हत्या करते है तो वही पर्चा छोड़ कर जाते है या दूसरे तीसरे दिन बैनर-पोस्टर लगाकर हत्या करने की जिम्मेदारी लेते है। सनकू राम गोटा की हत्या 26 जून को हुई थी, नक्सलियों ने इसकी जिम्मेदारी सप्ताह भर बाद ली है। कोयलीबेड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि 26 जून को सुबह 11 बजे ग्राम जूंगड़ा के सनकु राम गोटा की हत्या की सूचना को लेकर सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीण थाना आए थे।

थाना स्टाफ, परिजनों के सहयोग से मृतक के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोयलबेड़ा लाकर पोस्टमॉर्टम कराया गया।

धारदार हथियार से एमआर की हत्या

पड़ोसी बोला– घूर कर देखता था इसलिए मार डाला, कुछ दिनों बाद होने वाली थी शादी

रायपुर, 4 जुलाई (एजेंसियां)। रायपुर में एक मेडिकल प्रिजेंटेटिव का मर्डर हुआ है। टिकरापारा के मछली बाजार के पास पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने त्रिशूल नुमा थारदार हाथियार से उसकी जान ले ली। इस मामले में पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के बीच हुए आपसी झगड़े की वजह से बात इस कदर बिगड़ी कि इस विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। इस वारदात में मारे गए युवक का नाम कंचन मल है। मूलतः बंगाल का रहने वाला कंचन यहाँ अपने माता-पिता के साथ रहता था। उसके पिता फूलों का व्यवसाय करते थे। 22 साल के दीपक नामदेवे के साथ कंचन का 1 साल पुराना झगड़ा था ।



झगड़े का बदला लेने के चक्कर में ही हत्या की गई। पूछताछ में दीपक ने पुलिस को बताया है कि पिछले साल दुर्गा विसर्जन के वक्त दोनों के बीच विवाद हुआ था। आरोपी दीपक ने कहा कि कंचन मुझे घूर-घूर कर देखा करता था। रात को आरोपी जब घर लौट रहा था तो मैं मंदिर के पास उसे कंचन मिल गया दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इतने में

आरोपी दीपक ने कंचन पर चाकू से वार कर दिया। **मोहल्ले में दौड़ा-दौड़ा कर मारा**
नंदी चौक मछली बाजार के पास मंदिर के चबूतरे में आरोपी दीपक ने कंचन पर अटक किया । बुरी तरह से जख्मी कंचन खुद को बचाने के लिए गलियों में भागता रहा और पीछे थारदार हथियार लेकर दीपक उसे दौड़ाता रहा। गलियां खून से लाल नजर आईं। आखिरी वक्त में जब कंचन लोगों से मदद मांगने भाग रहा था तो उसके खून से सने पैरों के निशान भी गलियों में मौजूद हैं। कंचन बुरी तरह से जख्मी होकर अपने एक पड़ोसी के चौखट पर जाकर बैठ गया । जहां फिर से दीपक ने उस पर वार किया। देर रात शोर-शराबा

सुनकर आसपास के लोग भी जमा हुए यह देखकर दीपक भाग चुका था। फौरन स्थानीय लोग कंचन को अस्पताल लेकर गए जहां उसकी मौत हो गई । स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार किया । दीपक एग रोल सेंटर चलाता है। मोहल्ले में होने वाले पुराने झगड़ों में शामिल रहा है। अब इसके खिलाफ धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कंचन के पिता सुभाष चंद्र मल ने बताया कि हम कंचन की शादी की तैयारियां कर रहे थे। कुछ दिन बाद उसका विवाह होने वाला था। हम देर रात घर पर जाकर बैठ गया । जहां मैं फोन करके बताया कि आपके बेटे को किसी ने चाकू मार दिया है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 4 जुलाई (एजेंसियां)। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में चावल का संकट हो गया है। नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम लगभग खाली पड़े हैं। शासन के नियमानुसार गोदामों में तीन माह का चावल होना चाहिए, लेकिन एक महीने का ही शेष बचा है। यानी कुल भंडारण क्षमता का एक तिहाई से भी कम चावल ही उपलब्ध है। इस महीने पीछोपस में बंटने के बाद चावल का स्टॉक ही नहीं बचेगा। यह संकट राइस मिलर्स के दो महीने से सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) चावल नहीं जमा करने से खड़ा हुआ है। **गोदामों की क्षमता 15600 टन, उपलब्ध शिफ्ट 5000 टन**
जिले के वेयर हाउस कारपोरेशन के गोदामों की भंडारण क्षमता 15600 मीट्रिक



टन है। उनमें करीब 5000 मीट्रिक टन चावल ही शेष है। जबकि जिले में प्रतिमाह करीब 34880 क्विंटल चावल का राशन दुकानों में भंडारण होता है। राइस मिलों द्वारा चावल जमा नहीं करने से स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है। नया चावल नहीं आने से स्टॉक की भरपाई नहीं हो सकी। कस्टम मिलिंग का अनुबंध करने के बाद राइस मिलरो को उठाए गए धान

का चावल नागरिक आपूर्ति निगम को जमा करना होता है। **राइस मिलों से जल किया गया 2.05 टन चावल**
महीनों से राइस मिलर्स ने चावल जमा करना बंद कर दिया था एकदम से कम कर दिया था। इसके चलते गोदामों में चावल की कमी हुई, तब प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए नौ राइस मिलरो को चावल जमा करने के लिए लगातार नोटिस दिए। इसके बावजूद मिलर्स ने चावल जमा नहीं किए। इस पर राइस मिलों की जांच की गई। इसमें 80 मीट्रिक टन धान कम पाया गया। जिसके बाद राइस मिलरो के 2.05 लाख क्विंटल धान को जल किया गया। वहीं राइस मिलर्स का कहना था कि, 60 परसेंट धान में टूटा

होने से चावल जमा कर सके। **राइस मिलों पर चावल जमा करने का बना रहे दबाव**
प्रशासन ने असंतुष्ट होकर इस जवाब को नकार दिया, लेकिन दोषी राइस मिलरों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। जिला खाद्य अधिकारी श्वेता अग्रवाल ने बताया कि कि लगातार राइस मिलरो पर दबाव बना रहे हैं कि वे चावल जमा करें। इसके लिए बैठकें भी की गईं और नोटिस भी दिया गया, पर राइस मिलर चावल जमा नहीं कर रहे हैं। इसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रशासन एवं खाद्य विभाग लगातार मिलर्स पर दबाव बना रहा है कि दो दिन में चावल जमा करें। मिलर्स ने आश्वासन दिया है।

पुलिस कंट्रोल रूम में घुसा हाथी

जान बचाने छिपे कर्मचारी, कोरबा में महिला पर किया हमला

बालोद/कोरबा, 4 जुलाई (एजेंसियां)। छत्तीसगढ़ में लगातार हाथियों का उत्पात बढ़ता जा रहा है। अंबिकापुर, जशपुर, महासमुंद और कोरबा में उत्पात मचा रहे हाथी अब बालोद तक पहुंच गए हैं। दल से बिछड़कर एक हाथी सोमवार रात शहर में घुस आया। इसके चलते हड़कंप मच गया। हाथी पुलिस कंट्रोल रूम में घुस गया और वहां से साइबर सेल के दफ्तर जा पहुंचा। यह देखकर कर्मचारी जान बचाने के लिए अपने-अपने कार्यालय में छिप गए। वहीं दूसरी ओर कोखा में फल बीनने गई महिला पर हाथी ने हमला कर दिया। हमले में महिला घायल हो गई है।

केढ़ घंटे कंट्रोल रूम और आसपास घूमता रहा हाथी
दरअसल, बालोद शहर में तंदुला जलाशय से होता हुआ हाथी पुलिस कंट्रोल रूम तक

पहुंच गया। दंतैल हाथी को सामने देख पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए मेज-कुर्ची के नीचे छिप गए। रात करीब 9 बजे से 10.30 बजे तक हाथी वहीं इधर-उधर घूमता रहा। सबसे पहले आमापारा के लोक निर्माण विभाग के क्वार्टर और फिर वहां से पुलिस कंट्रोल रूम व साइबर सेल में पहुंच गया। वहां से निकलने के बाद मुख्य मार्ग होते हुए हाथी जुरी पापा की ओर बढ़ गया। इसके चलते शहर में भी डर फैल गया।

हाथी को देख गेट किया बंद, अंदर फंसे साइबर सेल के कर्मचारी

पुलिस कर्मियों ने बताया कि सबसे पहले साइबर सेल के सहायक उप निरीक्षक धरम भुआर्य ने हाथी को देखा। इसके बाद अन्य लोगों जानकारी दी। समय रहते आधे कर्मचारी कार्यालय को छोड़कर निकलने में

सफल हो गए, वहीं 15 से 20 कर्मचारी अंदर ही फंसे रहे। इसके बाद दोनों तरफ के चैनल गेट को बंद करके एक कमरे में छिपकर किसी तरह से पुलिसकर्मियों ने समय काटा। पुलिस कंट्रोल रूम में के पास ही कलेक्टर कुलदीप शर्मा का बंगला भी है। इसके चलते उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई।

लोहारा परिक्षेत्र के जंगल में पहुंचा हाथी

बताया जा रहा है कि, हांथी की वर्तमान लोकेशन कक्ष क्रमांक 288 आरएफ परिसर जाटादाह सहायक वृत्त गैँजी परिक्षेत्र लोहारा है। इसके बाद वन विभाग ने ग्राम बैहाकुआ, जाटादाह, शिवनी, पोपलाटोला, सहगांव, गैँजी, भालूकोहा, कामता ऊरेटा, गुगामी, भरदा पिंगाल, मरईटोला बोर्डरडीह में अलर्ट किया है। टीम लगातार पेट्रोलिंग भी कर रही है। यह हाथी करीब तीन वर्षों से सक्रिय है।

सूरजपुर, 4 जुलाई (एजेंसियां)। सूरजपुर जिले में बकरी की आंख कच्चा निगलने वाले एक शख्स की मौत हो गई। इससे पहले वो इसका मांस भी कच्चा ही खा रहा था। आंख व्यक्ति के गले में फंस गई, जिससे उसकी जान चली गई। घटना बसदेई चौकी क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक, मृत व्यक्ति बागर सिंह (45 वर्ष) सूरजपुर जिले के मदनपुर गांव का रहने वाला था। वो अपने रिश्तेदारों और 2 दोस्तों के साथ खोपा धाम गया हुआ था। यहां उसके किसी रिश्तेदार ने मन्नत पूरी होने पर बकरी की बलि दी। मांस को प्रसाद रूप में ग्रहण करने के लिए रिश्तेदार ले गए। वहीं बागर और उसके 2 दोस्त बकरे के सिर को ले आए। यहां शराब भट्टी से तीनों ने शराब खरीदी। मृतक बागर के साथी राकेश ने बताया कि तीनों खोपा धाम से सूरजपुर आ गए

और यहां जमकर शराब पी। वे लोग बकरी का सिर बनाने के लिए जा ही रहे थे कि बागर ने कहा कि उसे कच्चा मांस ही खाना है। यहां तक कि बाकी साथियों ने भी उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं मानी। उसने बकरे की आंख निकाली और खाने लगा। इसी दौरान आंख उसके गले में फंस गई। इससे सांस नली चोक हो गई। राकेश ने बताया कि उससे पानी पीने के लिए भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया।

काफी देर तक आंख बागर के गले में फंसी रही, लेकिन उसने पानी नहीं पिया, जिसके कारण दम घुटने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीण के साथी फिर भी उसे सूरजपुर के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची।

महिला की पीट-पीटकर हत्या

चतरा, 4 जुलाई (एजेंसियां)। झारखंड के चतरा में एक महिला को पीट-पीटकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि 30 जून को सदर थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों के एक समूह और एक जोड़े के बीच झगड़ा हो गया। समूह के लोगों ने महिला उसके साथी की पिटाई कर दी। इसमें महिला और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि पिटाई में घायल महिला का मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

बीजापुर, 4 जुलाई (एजेंसियां)। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हड़ताल पर बैठे संविदाकर्मियों ने मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया। नियमितीकरण की मांग कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि, कुंभकर्णीय नौद में सोई सरकार को जगाएंगे। साढ़े चार साल बीत गए, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। कर्मचारियों ने कहा कि, सरकार नियमितीकरण को लेकर अपनी

मंशा स्पष्ट करे। वहीं संविदा कर्मियों की इस हड़ताल का असर अब सरकारी कामकाज में दिखना शुरू हो गया है। दूर-दराज से आने वाले ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। **सरकारी मंशा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही**
कर्मचारियों ने कहा कि वर्ष 2018 में भी हम नियमितिकरण के लिए हड़ताल कर रहे थे। इसी तीन जुलाई के दिन कांग्रेस के

वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने घोषणा की थी कि कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 दिन में मांग पूरी करेंगे। उसीके बाद कांग्रेस ने घोषणा पत्र में भी शामिल किया, लेकिन तीन जुलाई 2023 के दिन यानी 5 साल बाद हमको सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार की मंशा वादा पूरा करने की दिखाई नहीं दे रही है। उनको इसे स्पष्ट करना चाहिए।

इमरान के खिलाफ तोशाखाना केस खारिज

इस्लामाबाद, 4 जुलाई (एजेंसियां)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे तोशाखाना केस को अयोग्य करार दे दिया है। इसके साथ ही खान की बेल एप्लिकेशन मंजूर कर दी गई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारुक ने ये फैसला सुनाया।

सुनवाई से पहले इमरान खान ने फारुक को हटाने की मांग की थी। खान के वकीलों ने सोमवार शाम हाईकोर्ट बंद होने के चंद मिनट पहले एक पिटीशन दायर की थी। इसमें कहा गया था- हमें लगता है कि चीफ जस्टिस तोशाखाना केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लें, क्योंकि उनके रहते इस केस की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती।

इमरान के वकीलों की दलीलें

इमरान के वकील गौहर खान ने यह पिटीशन दायर की थी। इसमें कहा गया था- जस्टिस फारुक के रहते हुए तोशाखाना केस की निष्पक्ष सुनवाई मुमकिन नहीं है। एक ऐसा बेंच बनाना चाहिए, जिसमें जस्टिस आमिर न हों।

पिटीशन के मुताबिक- कानून में इस बात की व्यवस्था है कि

इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बेल भी मिली, पूर्व पीएम ने कहा था- चीफ जस्टिस को हटाओ

अगर मुवक्किल चाहे तो वो किसी जज या चीफ जस्टिस को हटाने की मांग कर सकता है और इसके हजारों उदाहरण मौजूद हैं। यह केस बेहद अहम है और इसलिए ये जरूरी है कि सुनवाई सही और निष्पक्ष तरीके से हो। हमारे मुवक्किल इमरान खान को लगता है कि अगर चीफ जस्टिस बेंच में मौजूद होंगे तो उन्हें इंसाफ नहीं मिल सकेगा।

खास बात ये है कि इमरान के खिलाफ यह केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दायर किया गया है। इसमें किसी प्राईवेट पार्टी या सरकार का कोई लेनादेना नहीं है।

क्यों डर रहे हैं इमरान

‘द डॉन’ की सोमवार को पब्लिश रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान चीफ जस्टिस को सिर्फ इसलिए हटवाना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस आमिर बहुत ईमानदार और सख्त जज हैं और उन्होंने पहले दो मामलों में इमरान की जमानत खारिज की थी।

अब इस केस में इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को भी जांच एजेंसी के सामने पेश होना है। अब तक कुल 13 बार बुशरा को जांच एजेंसी ने पेश होने के लिए



नोटिस दिया है, लेकिन वो एक भी बार पेश नहीं हुई। इसके बाद जांच एजेंसी ने अखबारों में एक इश्तिहार निकलवाया और कहा कि अगर बुशरा बीबी पेश नहीं हुईं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल किए जाएंगे।

इसके बाद इमरान ने एक पिटीशन लाहौर हाईकोर्ट में दायर की। कहा- मेरी पत्नी घरेलू महिला हैं और उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा, उन्हें पूछताछ से राहत दी जाए। दूसरी तरफ, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान के खिलाफ बेहद पुख्ता सबूत हैं और यही वजह है कि वो किसी न किसी बहाने से सुनवाई की लंबे वक्त

तक लटकाना चाहते हैं।

क्या है तोशाखाना केस

चुनाव आयोग के सामने सत्ताधारी पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तोशाखाना गिफ्ट मामले को उठाया था। कहा था कि इमरान ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न देशों से मिले गिफ्ट को बेच दिया था। इमरान ने चुनाव आयोग को बताया था कि उन्होंने तोशाखाने से इन सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा था, बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे। बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी।

कैसे हुआ था खुलासा

करीब दो साल पहले अबराar

आतंक का सगना पाकिस्तान आतंकवाद से परेशान

इस्लामाबाद, 4 जुलाई (एजेंसियां)। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। दुनियाभर में घोषित आतंकवादी खुले घूम रहे हैं। लेकिन आज आतंकवाद को अपनी जमीन पर पनाह देने वाला पाकिस्तान खुद इससे परेशान है। इसका उदाहरण है कि एससीओ समिट में पाक पीएम शहबाज शरीफ ने आतंकवाद से दृढ़ विश्वास से निपटने की वकालत की। उन्होंने मंगलवार को आतंकवाद और उग्रवाद को कई सिर वाला राक्षस कहा। शहबाज ने कहा कि आतंकवाद चाहे व्यक्तियों, समूहों या राज्य स्तर पर हो उससे पूरी ताकत और दृढ़ विश्वास के साथ लड़ा जाना चाहिए। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक को वंचुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में भी बात की। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि आतंकवाद को राजनीतिक लाभ के लिए इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के किसी भी प्रलोभन में बचा जाना चाहिए।

खालिद नाम के एक पाकिस्तानी शख्स ने इन्फॉर्मेशन कमीशन में एक अजीब दायर की थी। कहा- इमरान को दूसरे देशों से मिले गिफ्ट्स की जानकारी दी जाए। जवाब मिला- गिफ्ट्स की जानकारी नहीं दी जा सकती। खालिद भी जद्दी निकले। उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान से पूछा था- आप तोहफों की जानकारी क्यों नहीं देते? इस पर खान के वकील का जवाब था- इससे मूलक की सलामती यानी सुरक्षा को खतरा है। दूसरे देशों से रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए अवाम को दूसरे देशों से मिले तोहफों की जानकारी नहीं दे सकते। पाकिस्तानी पत्रकार आरिफ अजाकिया और इमदाद अली शूमरो के मुताबिक- इमरान को सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) ने गोल्ड से बनी और हीरों से जड़ी बेशकीमती रिस्ट वॉच गिफ्ट की थी। उन्होंने ऐसी दो लिमिटेड एडिशन घड़ियां बनवाई थीं। एक खुद के पास रखी थी। दूसरी इमरान को गिफ्ट की थी। इसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए थी।

इंडियन डिप्लोमैट्स की हिफाजत करेंगे कनाडा-ऑस्ट्रेलिया

टोरंटो/कैनबरा, 4 जुलाई (एजेंसियां)। कनाडा में इंडियन डिप्लोमैट्स पर हमले की धमकी देने वाले खालिस्तान समर्थकों पर लगाम कसी जाएगी। कनाडा की फरिन मिनिस्टर मेलेनी जोली ने मंगलवार को कहा- हम भी वियना कन्वेंशन का हिस्सा हैं। लिहाजा, भारत के डिप्लोमैट्स की सिक्योरिटी के मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्रालय ने भी बिल्कुल यही बयान जारी किया।

सोमवार को हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस. जयशंकर ने अपने डिप्लोमैट्स पर हमले की धमकी को लेकर सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन से सफा कहा था खालिस्तान समर्थकों को किसी तरह की नाजायज छूट नहीं दी जानी चाहिए।

भारत से बातचीत कर रहा है

कनाडा

जयशंकर ने सोमवार को कनाडा में खालिस्तानियों की हरकतों पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए एक डिप्लोैमैटिक नोट

फिलाडेलफिया, 4 जुलाई (एजेंसियां)। अमेरिका में फिलाडेलफिया शहर के किंगसेसिंग में सोमवार रात मास शूटिंग की घटना सामने आई। गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

फिलाडेलफिया इंकवायरर के मुताबिक, जिस संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, उसने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी। उसके पास एक राइफल, एक हैंडगन और कई मैगजीन्स मौजूद थीं। उसने गोलीबारी क्यों की इसकी वजह अब तक सामने नहीं आई है।

पहले सुनाई दी गोली चलने की की आवाज, फिर मिले 4 शव

बीबीसी के मुताबिक सोमवार रात करीब 8:30 बजे एक पुलिस अधिकारी ने गोलियों की आवाज सुनी और साउथ 56वीं स्ट्रीट और चेस्टर एवेन्यू में एक घायल को देखा। इसके बाद कई लोगों ने पुलिस को इलाके में राइफल से लैस एक व्यक्ति के होने की जानकारी दी। छानबीन के दौरान पुलिस को 4 लोगों के शव मिले। इसके अलावा वहां मौजूद घायलों को तुरंत प्रेसबिटेरियन मेडिकल

भारत की सख्ती के बाद दोनों देश बोले- उन्हें पूरी सिक्योरिटी मुहैया कराई जाएगी

(डिमाशें) जारी किया था। इसमें कहा गया था कि खालिस्तान की मांग को प्रमोट करने वालों और इन हरकतों को भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे दोनों देशों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस बयान के कुछ देर बाद कनाडाई विदेश मंत्री ने जयशंकर से फोन पर बातचीत की थी।

इस बातचीत के बाद मंगलवार को मेलेनी जोली का बयान आया। उन्होंने कहा- हम भी वियना कन्वेंशन का हिस्सा हैं। लिहाजा, भारत के डिप्लोमैट्स की सिक्योरिटी के मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। बाद में ऑस्ट्रेलिया ने भी यही बयान जारी किया। कहा- हम भारत को प्यार दिलाते हैं कि उनके डिप्लोमैटिक स्टाफ को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। जोली ने आगे कहा-

हमारी सरकार भारत से लगातार बातचीत कर रही है। हमें जानकारी है कि भारत को खिलाफ कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज चल रही हैं और ये 8 जुलाई के इवेंट से जुड़ी हैं। कुछ लोगों की हरकतों को पूरी कम्युनिटी की आईडियोलॉजी नहीं समझा जाना चाहिए। कनाडा में जारी खालिस्तान समर्थकों की हरकतों पर भारतीय विदेश मंत्रालय और

अमेरिका के फिलाडेल्फिया में मास शूटिंग, 4 की मौत

बुलेटप्रूफ जैकेट पहने आरोपी गिरफ्तार शहर में इस साल हत्या के 212 मामले दर्ज

सेंटर पहुंचाया गया।

फिलाडेल्फिया में शूटिंग के मामलों में 19% की कमी

फिलहाल प्रशासन ने शूटिंग एरिया के आसपास रह रहे लोगों को सतर्क रहने और स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में आने तक अपने घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। फिलाडेलफिया में इस साल अब तक हत्या के 212 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि, ये पिछले साल की तुलना में 19% कम हैं।

गन वॉयलेंस आर्काइव की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में इस साल अब तक 300 से ज्यादा मास शूटिंग के मामले सामने आ चुके हैं। 2006 से लेकर अब तक अमेरिका में सामूहिक हत्या के 556 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।

अमेरिका की आबादी 33 करोड़ और यहां 40 करोड़ गन

नागरिकों के बंदूक रखने के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। स्विटजरलैंड के स्मॉल आर्म्स सर्वे यानी एसएएस की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में

मौजूद कुल 85.7 करोड़ सिविलियन गन में से अकेले अमेरिका में ही 39.3 करोड़ सिविलयन बंदूक मौजूद हैं। दुनिया की आबादी में अमेरिका का हिस्सा 5% है, लेकिन दुनिया की कुल सिविलियन गन में से 46% अकेले अमेरिका में हैं।

अक्टूबर 2020 के गैलप सर्वे के मुताबिक, 44% अमेरिकी वयस्क उस घर में रहते हैं, जहां बंदूकें हैं, इनमें से एक तिहाई वयस्कों के पास बंदूकें हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में 63 हजार लाइसेंसड गन डीलर थे, जिन्होंने उस साल अमेरिकी नागरिकों को 83 हजार करोड़ रुपए की बंदूकें बेची थीं।

अमेरिका 231 साल बाद भी अपने गन कल्चर को खत्म नहीं कर पाया है। इसकी दो वजह हैं। पहली- कई अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर वहां के राज्यों के गवर्नर तक इस कल्चर को बनाए रखने की वकालत करते रहे हैं। दूसरी- गन बनाने वाली कंपनियां, यानी गन लॉबी भी इस कल्चर के बने रहने की प्रमुख वजह है।

सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का ब्रिटेन ने खुलकर किया समर्थन

कहा– दुनिया में बढ़ा है कद



न्यूयॉर्क, 4 जुलाई (एजेंसियां)। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार का समर्थन किया है और कहा है कि भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील और अफ्रीकी देशों को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दी जाए। ब्रिटेन की प्रतिनिधि ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम 2020 में कदम रखें। बता दें कि अभी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पांच देश ही स्थायी सदस्य हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस शामिल हैं। हर दो वर्ष पर

इसके 10 देश अस्थायी सदस्य बनते हैं लेकिन भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने की मांग की जा रही है।

भारत समेत इन देशों को स्थायी सदस्यता देने की मांग

संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की स्थायी प्रतिनिधि बारबरा वुडवर्ड ने कहा कि हम चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए और इसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान और अफ्रीकी प्रतिनिधित्व को स्थायी जगह दी जाए। यह सही समय है, जब सुरक्षा परिषद 2020 में दाखिल

यूएस से जंग की तैयारी कर रहा चीन

वॉशिंगटन, 4 जुलाई (एजेंसियां)। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने की कोशिश में जुटी भारतीय मूल की निक्की हेली ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर तंज कसा है। निक्की ने चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा- कितनी हैरानी की बात है कि चीन इस वक्त जंग की तैयारियों में जुटा है और हमारे प्रेसिडेंट सियासत कर रहे हैं।

निक्की ने कहा- जेंडर इक्वालिटी के मुद्दे पर बातचीत या बहस पहले भी होती रही है और अब भी हो रही है, लेकिन हमारी नजर चीन पर होनी चाहिए जो अमेरिका से जंग की तैयारियों में जुटा है।

चीन की नेवी सबसे बड़ा खतरा

‘फॉक्स न्यूज’ को दिए इंटरव्यू में निक्की ने अमेरिका की सियासत और वर्ल्ड मैटर्स से जुड़े कई सवालों के खुलकर जवाब दिए। एक सवाल पर निक्की ने कहा- चीन ने हमारे देश के लिए

प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की रेस में शामिल निक्की हेली बोलीं– बाइडेन की नजर सिर्फ सियासत पर



सिक्योरिटी से जुड़े बड़े खतरे पैदा कर दिए हैं। वो अमेरिका से जंग की तैयारियों में जुटा है। हमारी सरकार को क्या तैयारियां हैं? हमारे यहां तो जेंडर इक्वालिटी पर बहस और सियासत चल रही है। बाइडेन इन्हीं बातों में बिजी हैं। यूएन में ऐंबेस्डर रह चुकीं निक्की ने आगे कहा- इस वक्त नेवी की सबसे बड़ी फ्लीट चीन के पास है। उसके 340 शिप्स हैं, तो हमारे पास सिर्फ 293 हैं। दो साल बाद चीन के पास 400

शिप होंगे और हमारे पास 350 भी नहीं होंगे। आज चीन हर रोज हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर रहा है। हमने तो इन पर अभी काम ही शुरू किया है। चीन पर एक और सवाल के जवाब में निक्की ने कहा- चीन की कोशिश है कि वो हर लिहाज और हर मोर्चे पर अमेरिकी मिलिट्री से ज्यादा ताकतवर बन जाए और इस पर वो बहुत तेजी से काम कर रहा है। हमारी मिलिट्री में अभी जेंडर इक्वालिटी पर बहस

चल रही है। यही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं। फरवरी में निक्की ने प्रेसिडेंट बाइडेन की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर गंभीर सवालिया निशान लगाते हुए एक सुझाव भी दिया था और इस पर बाइडेन की पत्नी जिल भड़क गई थीं। निक्की ने कहा था- सरकार में किसी भी बड़े पद पर काबिज 75 साल से ज्यादा उम्र के नेता का मेंटल एबिलिटी टेस्ट (तकनीकी भाषा में मेंटल कॉम्पिटेन्सी टेस्ट) मेंडेटरी होना चाहिए। प्रेसिडेंट जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन निक्की के इस सुझाव पर बिफर गईं। उन्होंने कहा- निक्की बकवास कर रही हैं। दरअसल, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रिपब्लिकन पार्टी और अमेरिकी मीडिया का एक हिस्सा बाइडेन की फिजिटल और मेंटल फिटनेस पर अकसर सवाल खड़े करते रहे हैं। इसके कई सबूत भी मौजूद हैं।

रूस बोला-यूक्रेन ने मॉस्को पर 5 ड्रोन से हमला किया

मॉस्को, 4 जुलाई (एजेंसियां)। रूस की राजधानी मॉस्को में मंगलवार को एक बार फिर ड्रोन अटैक हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का आरोप लगाया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोव्यानिन ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा- यूक्रेन ने मॉस्को में 5 ड्रोन से अटैक किया। हमने इन सभी को मार गिराया है। हालांकि, सुरक्षा के लिहाज से राजधानी के मुख्य एयरपोर्ट से कुछ घंटों के लिए फ्लाइट्स डायवर्ट कर दी गईं। रूस के रक्षा मंत्री ने बताया कि हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ है।

रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा- ये रूस पर एक और आतंकी हमला है। यूक्रेन ने मॉस्को के ऐसे क्षेत्र में हमला किया जहां आम नागरिक रहते हैं। यहां राजधानी का मेन एयरपोर्ट है जहां अक्सर विदेशी फ्लाइट्स भी आती रहती हैं। उन्होंने कहा- दुनिया को ये एहसास कराने की जरूरत है कि यूएनएससी के परमानेंट मेंबर अमेरिका, ब्रिटेन

हमने सभी को मार गिराया, अमेरिका-ब्रिटेन इस आतंकी देश की फंडिंग कर रहे



और फ्रांस आतंकी देश को मदद पहुंचा रहे हैं।

एयरपोर्ट के पास मिला 2 ड्रोन का मलबा

रूसी मीडिया आरटी के मुताबिक 2 ड्रोन का मलबा एयरपोर्ट से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर बरामद हुआ। कई चरमपंदावों ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे नोवाया क्षेत्र में धमाके की आवाज आई थी। मेयर सर्गेई ने इस क्षेत्र में 4 ड्रोन को मार गिराने की पुष्टि की है।

1 महीने पहले 2 बिल्डिंग पर 8 ड्रोन्स से हुआ था अटैक

टेक्सास में 10 हजार लोगों ने किया गीता पाठ

टेक्सास, 4 जुलाई (एजेंसियां)। अमेरिका के टेक्सास में सोमवार 10 हजार लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। गुरु पूर्णमा के मौके पर एलन ईस्ट सेंटर में 4 साल से लेकर 84 साल तक के लोगों ने पाठ किया। ये कार्यक्रम योग संगीता और एसजीएस गीता फाउंडेशन ने किया था। मैसूर के अवधूत दत्त पीठम को 1966 में गणपति सच्चिदानंद जी स्वामी ने स्थापित

बताया कि आध्यात्मिक संत गणपति सच्चिदानंद जी की मौजूदगी लोगों ने पाठ किया। ये सभी 10 हजार लोग सच्चिदानंद स्वामी से पिछले 8 सालों से जुड़े हुए हैं। स्वामी पिछले कई सालों से अमेरिका में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। अवधूत दत्त पीठम को 1966 में गणपति सच्चिदानंद जी स्वामी ने स्थापित

किया था। ये एक इंटरनेशनल स्परिचुअल, कल्चरल और सोशल वेलफेयर संगठन है। सच्चिदानंद जी स्वामी भगवद गीता का प्रचार करने और सनातन हिंदू धर्म के मूल्यों को फैलाने के लिए जाने जाते हैं। 14 जून को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में पहला हिंदू-अमेरिकन सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन को अमेरिकन्स फॉर

हिंदूज का नाम दिया गया था। सम्मेलन की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और प्राणिक के साथ हुई थी। इस सम्मेलन को 20 हिंदू संस्थाओं के समर्थन से कराया गया था। अमेरिकन-हिंदू सम्मेलन में फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, बोस्टन, टेक्सास, शिकागो, कैलिफोर्निया जैसे शहरों से करीब 130 भारतीय अमेरिकी नेता शामिल हुए थे।

पायलट की मांगों को मानने के सकेत

पेपरलीक करने पर उम्र कैद की सजा होगी, गहलोत ने की बिल लाने की घोषणा

जयपुर, 4 जुलाई (एजेंसियां)। राजस्थान में पेपरलीक करने वालों के खिलाफ गहलोत सरकार मौजूदा कानून को और कड़ा करने की तैयारी में है। सीएम ने पेपरलीक करने वालों को उम्र कैद की सजा करने का प्रावधान करने की घोषणा की है। इसके लिए विधानसभा में अगले सत्र में बिल लाया जाएगा। इसमे एंटी चीटिंग बिल में संशोधन करके उम्र कैद का प्रावधान किया जाएगा। सीएम ने RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया को सुधारने के लिए मैकेनिज्म बनाने की भी घोषणा की है। सीएम अशोक गहलोत की इस घोषणा को पेपरलीक पर सचिन पायलट की मांगों को मानने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसे पायलट के साथ सुलह फार्मूले की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।

सीएम अशोक गहलोत ने टवीट करके नकल करने वालों को उम्र कैद की सजा करने और भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार की



घोषणा की। सीएम ने लिखा-राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी और दूसरे हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। पेपरलीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल

लाने का फैसला किया है।

पायलट की मांगें मानकर सुलह के संकेत इसलिए

सीएम अशोक गहलोत की इस घोषणा को सचिन पायलट की मांगों को मानने की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। सचिन पायलट ने आरपीएससी को भंग करके इसका पुनर्गठन करके आमूलचूल बदलाव करने की मांग की थी। अब तक पायलट की मांगों को गहलोत ने सिरे से

खारिज कर दिया था। पायलट ने 11 से 15 मई तक पेपरलीक और बीजेपी राज के करप्शन के खिलाफ अजमेर से जयपुर तक पैदल यात्रा की थी।

15 मई को जयपुर में यात्रा खत्म करके सभा में पायलट ने सरकार के सामने तीन मांगें रखते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम खत्म होने से पहले 29 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की मौजूदगी में गहलोत पायलट की सुलह बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद पायलट ने आंदोलन तो नहीं किया, लेकिन युवाओं से जुड़ी मांगों को छोड़ने से इनकार कर दिया था।

पायलट का युवाओं से जुड़ी मांगों पर जोर था, उन्हें पूरा करने के लिए बीच का रास्ता निकाला। सचिन पायलट ने पेपरलीक से प्रभावित युवाओं को मुआवजा देने , आरपीएससी को भंग करके पुनर्गठन करने और बीजेपी राज के करप्शन की जांच के लिए हाईपावर कमेटी बनाने की मांग

की थी। सीएम ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए RPSC, कर्मचारी चयन बोर्ड की कामकाज की शैली और प्रोसेस को सुधारने की शुरुआत करने की घोषणा की है। आज की सीएम की घोषणा को पायलट की मांग को मानने के लिए बीच का रास्ता निकालने से जोड़कर देखा जा रहा है।

सीएम ने पहले बुद्धि का दिवालियापन बताया था, अब रुख बदला

सचिन पायलट की तीन मांगों को मानने से पहले सीएम अशोक गहलोत ने साफ इनकार कर दिया था। पेपरलीक से प्रभावित बेरोजगारों को मुआवजा देने की मांग को गहलोत ने बुद्धि का दिवालियापन बताया था। आरपीएससी को भंग करने की मांग पर गहलोत ने कहा था कि पायलट हमारे परिवार के मेंबर हैं, उन्होंने बात उठाई है तो हमने परीक्षण करवाया तो सामने आया कि कानून में इस तरह का प्रावधान ही नहीं है।

सांसद बोलीं- कांग्रेस मंत्री-विधायकों के घरवाले ही निकलते हैं रेपिस्ट

जसकौर ने कहा- कांग्रेस सरकार के खिलाफ थाली-

चम्मच लेकर आज जयपुर पहुंचेंगी महिलाएं

दौसा, 4 जुलाई (एजेंसियां)। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने सोमवार को कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कहा- महिलाओं के प्रति कांग्रेस संवेदनशील नहीं है। कांग्रेस के विधायक हों या मंत्री, उनके परिजन ही दुष्कर्म निकलते हैं।

सांसद जयपुर में 5 जुलाई को प्रस्तावित विधानसभा घेराव की तैयारी बैठक में दौसा भाजपा कार्यालय में बोल रही थीं। यह घेराव भाजपा महिला मोर्चा की ओर से किया जाएगा।

सांसद ने कहा कि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार महिलाओं के खिलाफ शुरू से ही असंवेदनशील थी। महिलाओं के प्रति कांग्रेस सरकार का जो रवैया रहा है, उससे न तो महिलाओं को सम्मान मिला और न ही सुरक्षा। 5 जुलाई को थाली-चम्मच



लेकर पहुंचेंगी महिलाएं

राज्य की कांग्रेस सरकार को विदा करने के लिए अब महिलाओं को आगे आना होगा। इसके लिए 5 जुलाई को थाली-चम्मच लेकर और काली पट्टी बांधकर महिलाएं जयपुर पहुंचेंगी। वहां सरकार को जगाने का काम करेंगे।

सांसद ने कहा कि राजस्थान के हर जिले से महिला कार्यकर्ता

जयपुर पहुंचकर सरकार की अंतिम सांस को तोड़ने का प्रयास करेंगी। प्रदेश में महिला उत्पीड़न चरम पर है। महिला उत्पीड़न के 10 हजार से भी ज्यादा के सामने आ चुके हैं।

रोजाना महिला उत्पीड़न के 17 केस सामने आ रहे हैं। इन मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

प्रदेश मंत्री गुर्जर ने कांग्रेस सरकार को घेरा

भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश मंत्री नीलम गुर्जर ने भी महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर सरकार को घेरा। कहा- पिछले साढ़े चार साल में महिला अपराध चरम पर हैं। जिसे रोकने के लिए राज्य सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। ऐसी सरकार को प्रदेश की जनता जल्द ही विदा कर देगी।

राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ एबीवीपी ने खोला मोर्चा

12 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, बोले- छात्रों पर बेवजह किया लाठीचार्ज

जयपुर, 4 जुलाई (एजेंसियां)। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी कैम्पस में विरोध मार्च निकाल यूनिवर्सिटी प्रशासन को 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया। तो एबीवीपी के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। जिसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन जिम्मेदार होगा।

एबीवीपी के जयपुर प्रांत के संगठन मंत्री उपमन्यु राणा ने कहा कि सरकार चाहे कितना ही लाठीचार्ज क्यों न करले। एबीवीपी के कार्यकर्ता और डरने वाले नहीं हैं। हम आम छात्रों की मांगों को लेकर लगातार संघर्ष करते आए थे। छात्रों के लिए आगे भी संघर्ष करेंगे। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी



प्रशासन द्वारा आम छात्रों की जायज मांगों को पूरा नहीं किया गया। तो हम प्रदेशभर में सड़कों पर उतर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। ताकि छात्र विरोधी सरकार की हकीकत आम छात्रों तक पहुंच सके।

राजस्थान यूनिवर्सिटी एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष भरत भूषण यादव ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा बेवजह छात्रों पर लाठीचार्ज

करवाया गया। जिसमें कई छात्रों को गंभीर चोटें भी आई हैं। जबकि आम छात्र सिर्फ अपनी जायज मांगों को सिंडिकेट बैठक में पहुंचाना चाहते थे। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों की समस्याओं को सुनने की जगह उन्हें लाठियों से पिटाया दिया।

यूनिवर्सिटी की इस बर्बरता को आम छात्र कभी नहीं भूलेगा। ऐसे में अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा

हमारी 12 सूत्री मांगों को पूरा करने के साथ ही सिंडिकेट की बैठक में हुए फैसलों को लागू नहीं किया गया। तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। जिसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस दौरान छात्रनेता मनु दाधीच, देव पलसानिया समेत बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी परिसर में पुलिस का हस्तक्षेप रोका जाए। मानवीकी पीठ सभागार को तुरंत शुरू किया जाए। राजस्थान यूनिवर्सिटी की शोध प्रवेश परीक्षा पीपीटी की दिनांक निश्चित की जाए। शैक्षणिक au अशैक्षणिक के रिक्र पदों पर तुरंत नियुक्ति की जाए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्नातक व स्नातकोतर की सीटों में वृद्धि की जाए। छात्रवासों की सीट बढ़ाई जाए व नये हॉस्टल का निर्माण किया जाए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में समय समय पर प्लेसमेंट की व्यवस्था की जाए।

जयपुर, उदयपुर और अलवर में 2 इंच तक बारिश

रेगिस्तानी जिलों में पारा 40 के पार; उमस-गर्मी से लोग परेशान

जयपुर, 4 जुलाई (एजेंसियां)। राजस्थान में आजकल अलग-अलग तरह के मौसम देखने को मिल रहे हैं। जहां पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश का दौर जारी है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में गर्मी और उमस तेज होती जा रही है। सोमवार को जयपुर, उदयपुर, अलवर समेत 10 से ज्यादा जिलों में एक से लेकर दो इंच तक बरसात हुई। बारिश के साथ ही इन शहरों में उमस भी तेज रही।

उधर , जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत अन्य शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। मौसम विभाग ने बुधवार देर शाम से राजस्थान में एक नया सिस्टम एक्टिव होने और 6 जुलाई से कई हिस्सों में अच्छी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई

है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो अलवर, बारों, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, कोटा, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर में 5 से लेकर 54मिमी तक बरसात हुई।

सबसे ज्यादा बरसात अलवर के तिजारा में 54मिमी रिकॉर्ड की गई। इन जिलों में बारिश के साथ उमस भी बनी हुई है।

जयपुर में कल दिगंबर तेज गर्मी और उमस रही। रात में भी मौसम परेशान करने वाला ही रहा। हालांकि कल देर शाम जयपुर के ग्रामीण इलाके रामगढ़ बांध, जमवारामगढ़, पावटा, बस्सी, चाकसू, कोटखावदा समेत कई जगह अच्छी बारिश हुई। बस्सी में 42मिमी बरसात दर्ज हुई।

डिस्कॉम एसई की टेबल पर महिलाओं ने फेंकी चूड़ियां

जिले की समस्या को लेकर किया डिस्कॉम का घेराव, 15 दिन में सही करने का मिला आश्वासन



जैसलमेर, 4 जुलाई (एजेंसियां)। जैसलमेर में पिछले लंबे समय से बिजली की समस्या को लेकर शहर में भारी रोष को देखते हुए बीजेपी ने बिजली घर का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जैसलमेर एसई

जीवान राम गर्ग की टेबल पर चूड़ियां फेंककर अपना विरोध दर्ज करवाया। बी जे पी पदाधिकारियों ने एससी ऑफिस में धरना लगाकर प्रदर्शन किया। इससे पहले हनुमान चौराहे पर एक आमसभा का आयोजन किया गया। सभा में सभी ने शहर में बिजली की ओर मिचौली को लेकर डिस्कॉम और जनप्रतिनिधियों को जमकर कोसा। बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय

कार्यकारिणी के सदस्य आईदान सिंह भाटी ने बताया कि शहर में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में भीषण गर्मी के दौरान बिजली की लगातार अछोषित कटौती से परेशान है। शहर में रात को भी बिजली काट दी जाती है और बिजली घर के अधिकारी फोन बंद कर लेते हैं। लोग रात-रात भर बिजली नहीं होने से परेशान रहते हैं। ऐसा लगातार कई दिनों से जारी है और इसको लेकर लोगों में भी भारी रोष है। भाटी ने बताया कि दो से अधिकारी और ना ही जनप्रतिनिधि जनता की परेशानी को लेकर गंभीर है।

जितने भी कुंवारे हैं उनकी लिस्ट दो, सभी की कराऊंगा शादी मामचारी गांव में बोले बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा



करौली, 4 जुलाई (एजेंसियां)। करौली के मामचारी गांव में भाजपा से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने गांव वालों से कहा कि यहां जितने भी कुंवारे हैं उनकी लिस्ट मुझे दे दो, मैं सभी की शादी करा दूंगा। भाजपा से राज्यसभा सांसद

किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। करौली जिले के मामचारी गांव में उन्होंने सरकार और मंत्री रमेश मीणा का नाम लिए बिना गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन फिर भी मैं

कहना चाहूंगा कि यहां लोग लूटने में लगे हुए हैं। जिसमें मंत्री के भाई, मंत्री के दामाद, मंत्री के बहनोई, मंत्री की बहन सब के सब लूटने में लगे हुए हैं। इन्होंने पूरे राजस्थान को लूट लिया। राजस्थान में जितनी भी खाने चल रही हैं उसमें गहलोत सरकार के राज में 66,000 करोड़ का घोटाला किया गया है। ये अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है।

मामचारी गांव के दौरे के दौरान सांसद मीणा ने एक दंगल कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं मामचारी के लिए एक बड़ी घोषणा करना चाहता हूं, यहां जितने भी कुंवारे हैं, उन सब की लिस्ट मुझे दे दो, मेरे क्षेत्र महवा से मैं सभी की शादी करा दूंगा।

उदयपुर में अवैध शराब पकड़ी

अलग-अलग ब्रांड के 374 कार्टन मिले

उदयपुर, 4 जुलाई (एजेंसियां)। उदयपुर-अहमदाबाद हाइवे पर आबकारी विभाग ने नाकेबंदी के दौरान शराब से भरा कंटेनर पकड़ा है। इसमें करीब 28.86 लाख रुपए की अवैध शराब थी। इस मामले में ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। खेरवाड़ा के आबकारी वृत निरीक्षक जितेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि विभाग के विशेष अभियान के तहत अहमदाबाद हाइवे पर खेरवाड़ा-उदयपुर के बीच नाकाबंदी की गई। इसी दौरान एक कंटेनर को रकवाया गया।

उदयपुर की ओर से महाराष्ट्र नंबर के कंटेनर की जांच की गई तो

उसमें विभिन्न अंग्रेजी ब्रांड की अवैध शराब के कार्टन पड़े थे। टीम ने कंटेनर को जब्त कर आबकारी थाना परिसर ले गई और वहां पर गिनती की गई। इसमें पंजाब निर्मित अलग-अलग ब्रांडों के 374 कार्टन पाए गए जिसकी कुल कीमत करीब 28.86 लाख रुपए आंकी गई। इस मामले में आरोपी कंटेनर चालक हरियाणा के जींद निवासी सतपाल पुत्र मेहर सिंह को गिरफ्तार किया है। टीम में खेरवाड़ा के प्रहराधिकारी धोलाराम विश्रोई, मांगीलाल, बंशीलाल, अमृतलाल, सोहनलाल, जगदीश आदि शामिल थे।

मासूम बेटी के साथ ट्रेन के नीचे आया पिता बेटी को लेकर चलती ट्रेन में चढ़ रहा था, बैलेंस बिगड़ा तो दोनों गिरे

आबूरोड, 4 जुलाई (एजेंसियां)। चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक पिता अपनी 5 साल की बेटी के साथ गिर गया। हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई। अपनी आंखों के सामने पति और बेटी को ट्रेन की चपेट में आते देख पत्नी बेहोश हो गई। मामला सिरौही जिले के आबूरोड रेलवे स्टेशन का है। घटना 2 जुलाई की है, जिसका वीडियो मंगलवार को सामने आया है। भीमाराम (36) अपनी पत्नी जीवी (30) और 2 जुड़वा बेटियों रंजीता (5) और मोनिका (5) के साथ अपने गांव भैंसावाड़ा तहसील आहोर (जालोर) जाने के लिए निकला था। आबूरोड रेलवे स्टेशन पर रिवार दोपहर करीब 12.35 बजे साबरमती-जोधपुर पैसेंजर ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 1 पर आई। भीमाराम अपने परिवार के साथ ट्रेन रवाना होने से कुछ मिनट पहले ही स्टेशन पहुंचा था। स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन चलने लग गई। आनन-फानन में

भागते हुए बेटी रंजीता को ट्रेन में चढ़ा दिया। पत्नी जीवी दूसरी बेटी मोनिका के साथ पीछे रह गईं। भीमाराम ने भागते हुए बेटी मोनिका को पत्नी की गोद से लिया और वापस ट्रेन की तरफ दौड़ा। भीमाराम अपनी दूसरी बेटी मोनिका को गोद में लेकर चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था कि बैलेंस बिगड़ने से ट्रेन-प्लेटफार्म की बीच वाली जगह पर गिर गया।

हादसे के बाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना के तुरंत बाद जीआरपी पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को बाहर निकालकर आबूरोड के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों के शव को मॉर्चुरी में रखवाया और पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

अन्याय और शोषण के खिलाफ अल्लूरी सीताराम राजू का संघर्ष अविस्मरणीय : राष्ट्रपति

स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का बलिदान सराहनीय : केसीआर

हैदराबाद, 4 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नगर में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के समान समारोह में भाग लिया और संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि अन्याय और शोषण के खिलाफ अल्लूरी सीताराम राजू का संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक गौरवशाली अध्याय है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों, विशेषकर युवा पीढ़ी को उनकी देशभक्ति और साहस से अवगत होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि अल्लूरी सीताराम राजू का जीवन चरित्र जाति और वर्ग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समाज को एकजुट करने का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अल्लूरी सीताराम राजू को आदिवासी समाज ने पूरी तरह से अपना लिया था और उन्होंने आदिवासी समाज के सुख-दुख को भी अपना सुख-दुख बनाया। उन्हें एक आदिवासी योद्धा के रूप में याद किया जा रहा है और यही उनकी असली पहचान है। वे अपनी शहादत तक आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की विरासत को याद रखना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने बुद्धिजीवियों, विशेषकर समाजशास्त्रियों और इतिहासकारों से सभी नागरिकों, विशेषकर युवा



पीढ़ी के बीच अल्लूरी सीताराम राजू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों की भलाई के लिए निस्वार्थ और निडर होकर काम करना अल्लूरी सीताराम राजू के जीवन का संदेश है। उन्होंने कहा कि हम उनके आदर्शों को अपने आचरण में अपनाकर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उन्होंने सभी से समाज और देश के हित में अल्लूरी सीताराम राजू के मूल्यों और आदर्शों को अपनाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में दौरान मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू को

याद करते हुए कहा कि देश की आजादी के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने वाले इस स्वतंत्रता सेनानी का बलिदान सराहनीय है। स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि ब्रिटिश शासन और आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ने वाले सीताराम राजू ने देश के लिए कई बलिदान दिए हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग इस स्वतंत्रता सेनानी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह के समान समारोह का ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित करना बड़ी बात है, जिसमें

राष्ट्रपति भी भाग ले रही हैं। सीएम केसीआर ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने भी अल्लूरी सीताराम राजू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अल्लूरी को भारत की संस्कृति, जनजातीय पहचान, वीरता, आदर्शों और मूल्यों का प्रतीक बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन आदिवासी समाज के अधिकारों और उनके उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। मंत्री ने कहा, उनका बलिदान और जीवन यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है।

कलेक्टर ने आदिलाबाद में आदिवासी व्यक्ति को सहायता का आश्वासन दिया



आदिलाबाद, 4 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। कलेक्टर पीएस राहुल राज ने एक आदिवासी व्यक्ति को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया, जिसकी पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने मंगलवार को नेराडीगोंडा मंडल के चिंचोली गांव में पीड़िता को सांत्वना दी। राज ने पीड़ित के बेटे को शिक्षा और छात्रावास की सुविधा प्रदान करने और आदिवासी व्यक्ति को एक घर स्वीकृत करने का वादा किया। जेडपीटीसी सदस्य अनिल जाधव और अधिकारी उपस्थित थे।

आदिवासी अधिकार संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। 20 जून को 35 वर्षीय महिला से बलात्कार और हत्या के आरोप में तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। वे सुमुखराव संतोष, पसारे संतोष और शेख खादोर थे, जो इंद्रवेली मंडल के धनोरा-बी गांव से थे।

गुप्ता ने कांग्रेस नेताओं से पूछा सवाल

कांग्रेस शासित राज्य 4,000 रुपये की आसरा पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं?

नलगोंडा, 4 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। तेलंगाना राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष गुप्ता सुखेंद्र रेड्डी ने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं से पूछा कि कांग्रेस शासित राज्यों में प्रति माह 4,000 रुपये की आसरा पेंशन क्यों लागू नहीं की जा रही है, जैसा कि राहुल गांधी ने खम्मम सार्वजनिक बैठक में तेलंगाना के लोगों से वादा किया था।

यहां मीडिया से बात करते हुए गुप्ता सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस नेता बीआरएस सरकार के खिलाफ कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं, जो लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की



विफलता के कारण भाजपा केंद्र में सत्ता में आई थी। राष्ट्रीय राजनीति में वैकल्पिक राजनीतिक ताकत के लिए प्रयास कर रहे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की आलोचना करने का कांग्रेस नेताओं को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आसरा पेंशन पर खम्मम की सार्वजनिक बैठक में कांग्रेस द्वारा

सरकार ने कुमराम भीम से प्रेरणा लेकर योग्य आदिवासियों को पट्टा दिया : इंद्रकरण

आदिलाबाद, 4 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। वन मंत्री अल्लोला इंद्रकरण रेड्डी ने मंगलवार को उटूर् मंडल केंद्र में उटूर्, सिरिकोडा और इंद्रवेली मंडल के पात्र आदिवासियों को पोडू भूमि पट्टे सौंपे। विधायक रेखा नाइक और राठोड़ बापू राव भी उपस्थित थे।

लाभार्थियों को संबोधित करते हुए, रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासी किंवदंती कुमराम भीम से प्रेरणा लेकर योग्य आदिवासियों को पट्टे देने के लिए कदम उठाए हैं, जिन्होंने जल, जंगल और जमीन पर अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। पट्टा धारकों को रायथु बंधु योजना के तहत भी वित्तीय सहायता मिलेगी। मंत्री ने कहा कि आदिलाबाद में 31,688 एकड़ वन भूमि पर गिरि विकासम योजना के तहत



रियायती कीमतों पर बिजली की मोटों और खेत के कुएं उपलब्ध कराने के अलावा, आदिवासी किसानों को तीन चरण के बिजली कनेक्शन भी दिए जाएंगे। आदिलाबाद कलेक्टर पीएस राहुल राज और आईटीडीए-उटूर् परियोजना अधिकारी चाहत बाजपेयी उपस्थित थे।

पीएम ने साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया

मोदी वर्चुअली जुड़े, कहा- यहां अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े पूरी दुनिया के विद्वान इकट्ठा होंगे

अमरावती, 4 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंध्र प्रदेश के पुडुपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इसे सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट ने बनवाया है। प्रशांति निलयम सत्य साईं बाबा का मुख्य आश्रम है। यह बिल्डिंग लगभग 56 हजार 500 वर्ग फुट में बनाई गई है। इसमें दो सभागार हैं, दोनों में ही एक-एक हजार लोगों के बैठने की क्षमता है। कन्वेंशन सेंटर के इन्फॉरमेशन के बाद प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम देश-विदेश से शामिल लोगों को संबोधित किया। पीएम ने कहा, इस पूरे आयोजन में श्री सत्य साईं की प्रेरणा और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। मैंने इस कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें देखी हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, इस सेंटर में आध्यात्मिकता की अनुभूति भी है और आधुनिकता की आभा भी है। इसमें सांस्कृतिक विद्यता भी है और वैचारिक भव्यता भी है। यहां अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े पूरी दुनिया के विद्वान इकट्ठा होंगे। मोदी ने कहा, श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा



है। इस सेंटर में आध्यात्मिकता की अनुभूति भी है और आधुनिकता की आभा भी है। इसमें सांस्कृतिक विद्यता भी है और वैचारिक भव्यता भी है। यहां अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े पूरी दुनिया के विद्वान इकट्ठा होंगे। मोदी ने कहा, श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा

है। इस सेंटर में आध्यात्मिकता की अनुभूति भी है और आधुनिकता की आभा भी है। इसमें सांस्कृतिक विद्यता भी है और वैचारिक भव्यता भी है। यहां अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े पूरी दुनिया के विद्वान इकट्ठा होंगे। मोदी ने कहा, श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा

श्री अन्न से बना भोजन दे रहा है, ये भी एक बहुत सराहनीय पहल है। इस तरह के काम से दूसरे राज्यों को भी जोड़ा जाए तो देश को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। श्री अन्न में स्वास्थ्य भी है और संभावनाएं भी हैं। हमारे ऐसे सभी प्रयास वैश्विक स्तर पर भारत के सामर्थ्य को बढ़ाएंगे और भारत की पहचान को मजबूती देंगे।

सत्य साईं बाबा ने देश में तीन मंदिर स्थापित किए थे : सत्य साईं बाबा एक आध्यात्मिक गुरु थे। उनके बचपन का नाम सत्यनारायण राजू था। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के पुडुपर्थी गांव में 23 नवंबर 1926 को हुआ था। बाबा को प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु शिरडी के साईं बाबा का अवतार माना जाता है। वे अपने माता-पिता की 8वीं संतान थे। 8 साल की उम्र में बाबा ने भजनों की रचना करनी शुरू कर दी थी। 24 अप्रैल 2011 को उन्होंने महासमाधि ले ली थी। उन्होंने भारत में तीन मंदिर स्थापित किये थे। इसमें मुंबई में धर्मक्षेत्र, हैदराबाद में शिवम और चेन्नई में सुंदरम शामिल हैं। इनके अलावा दुनियाभर के 114 देशों में सत्य साईं केंद्र बने हुए हैं।

विकास कार्यों के पूरे होने के साथ धर्मपुरी मंदिर शहर का बदल गया चेहरा

जगतियाल, 4 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। विभिन्न विकास कार्यों के पूरा होने के साथ धर्मपुरी मंदिर शहर का चेहरा बदल गया है। मंदिरों के साथ-साथ मंदिर शहरों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, राज्य सरकार ने धर्मपुरी के पुनरुद्धार और इसे मंदिर शहर के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया था।

लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर और उसके संबद्ध मंदिरों के विकास के अलावा, आंतरिक सड़कों का निर्माण, शहर का सौंदर्यीकरण और अन्य कार्य 141 करोड़ रुपये से किए गए। मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने परिवार के सदस्यों के साथ जुलाई 2015 में धर्मपुरी में आयोजित गोदावरी पुष्करलु में भाग लिया था। मुख्यमंत्री ने अगस्त 2019 में फिर से मंदिर का दौरा किया था। अपनी यात्राओं के दौरान, उन्होंने मंदिर और शहर को सभी मोर्चा पर विकसित करने का वादा किया। जबकि मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपये मंजूर किए, 2018 में धर्मपुरी को नगरपालिका के रूप में अपग्रेड करने के बाद 25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। स्थानीय विधायक और कल्याण मंत्री कोणुला ईश्वर ने मंदिर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए। डीएमएफटी फंड से अन्य 6 करोड़ रुपये भी जारी किए गए।

आंतरिक सड़कों के विस्तार और बिछाने के अलावा, 11.10 करोड़ रुपये खर्च करके गोदावरी नदी की शुद्धता की रक्षा के लिए जल निकासी का भी निर्माण किया गया। धर्मपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 6.30 करोड़ रुपये खर्च कर विकसित किया गया है। 30 बिस्तरों वाले अस्पताल को 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड करने के अलावा, एक डायलिसिस सेंटर, ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू बेड की भी व्यवस्था की गई। 50 करोड़ रुपये से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र का काम शुरू किया गया। स्वास्थ्य मंत्री टी. हरीश राव ने भी केंद्र के लिए 4.50 करोड़ रुपये मंजूर करने का आश्वासन दिया है।

महिला ने चुरा ली ग्राहक की 30 लाख की अंगूठी

पोल खुलने के डर से टॉयलेट में फेंक दी, पुलिस ने पकड़ा हैदराबाद, 4 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। हैदराबाद के पांश जुबली हिल्स में स्थित क्लिनिक गई महिला ग्राहक की हीर की अंगूठे वहां काम करने वाली कर्मचारी ने चुरा ली, लेकिन पकड़े जाने के डर से महिला कर्मचारी ने 30.69 लाख की हीर की अंगूठी को टायलेट में बहा दिया। पुलिस बताया कि महिला कर्मचारी ने डर की वजह से ऐसा कदम उठाया था। मामला हैदराबाद के पांश जुबली हिल्स का है। यहां पिछले हफ्ते एक त्वचा और बाल क्लिनिक पर एक महिला ग्राहक बाल हटाने को लेकर अपने काम से क्लिनिक गई थी, जब प्रक्रिया शुरू होने वाली थी तो महिला कर्मचारी ने उसे अंगूठी को एक बाक्स में रखने के लिए कहा। लेकिन जब क्लिनिक से सभी काम करने के बाद महिला ग्राहक घर लौटी उसे पता चला कि वह क्लिनिक में अपनी अंगूठी भूल गई है। जब वह पूछताछ के लिए क्लिनिक लौटी तो उसे वहां कोई जानकारी नहीं दी गई। जब उसे वहां कुछ शक हुआ तो उसने मामले की शिकायत पुलिस में कर दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और कर्मचारियों से पूछताछ की, जिसके बाद महिला कर्मचारी जिसने अंगूठी उठाई थी ने कथित तौर पर पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने अंगूठी चुराई थी और इसे अपने पर्स में रखा था।

अधिकारी ने कहा, लेकिन उसने कहा कि बाद में पुलिस के हाथों पकड़े जाने के डर से उसने इसे क्लिनिक के वॉशरूम में फ्लश कर दिया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान, पुलिस ने प्लंबर की मदद से कमांड को जोड़ने वाली पाइपलाइन से अंगूठी बरामद कर ली और बाद में महिला कर्मचारी को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।

करोड़ों रुपये की ठगी कर तेलंगाना से लड़ा विधानसभा चुनाव, पुलिस ने किया गिरफ्तार

हैदराबाद, 4 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स ने करोड़ों रुपये की ठगी कर तेलंगाना में विधानसभा चुनाव भी लड़ा। हालांकि, विधानसभा चुनाव में इसे जीत हासिल नहीं हो पाई।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, एक निजी कंपनी के निदेशक ने शिकायत देकर कहा कि उन्हें चीन से 50 हजार मीट्रिक टन लौह अयस्क भेजने का ऑर्डर मिला था। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ ऐसे व्यापारियों की तलाश थी, जो

इतनी बड़ी मात्रा में लौह अयस्क स्पलाई कर पाएं। आरोपी सिद्धार्थ रेड्डी दिल्ली आया और उसने कहा कि उसकी कंपनी पूरा लौह अयस्क स्पलाई कर देगी। ऐसे में दोनों कंपनियों के बीच एग्रीमेंट हो गया। आरोपी ने 6 करोड़ रुपये से ज्यादा ले भी लिये, लेकिन न तो लौह अयस्क स्पलाई किया और न ही पैसे वापस लौटाए। पुलिस के मुताबिक, आरोपी सिद्धार्थ रेड्डी ने उसी पैसे से तेलंगाना में 2014 में विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। अब वह पुलिस के हथिय बढ़ गया है।

शिवाजी मूर्ति के पास कथित तौर पर पेशाब : झड़प के बाद तनाव

हैदराबाद, 4 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। शिवाजी की मूर्ति के पास कथित तौर पर पेशाब करने पर एक व्यक्ति पर हमला किए जाने के बाद तेलंगाना में सिद्दीपेट जिले के गजवेल शहर में दो समूहों के बीच झड़प हो गई जिसके बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया। नशे की हालत में उस व्यक्ति को शिवाजी की मूर्ति के पास पेशाब करने के लिए सजा देते हुए उसे नग्न घुमाया गया। इस घटना के कारण विभिन्न समुदायों के समूहों के बीच झड़प हो गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल भी हुआ। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को यह आश्वासन देकर शांत किया कि वे इसमें शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेंगे। घटना के विरोध और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कुछ संगठनों ने मंगलवार को गजवेल में बंद का भी आह्वान किया। गजवेल

विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव करते हैं। इस बीच मजलिस बचाओ तहरीक (एमबीटी) के नेता अमजदुल्ला खान खालिद ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस घटना पर मूकदर्शक बनी रही। उन्होंने पुलिस महानिदेशक और सिद्दीपेट आयुक्त से जांच का आदेश देने का आग्रह किया, साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सुरक्षा की मांग की।

स्वतंत्र वार्ता

Email :
svaarthta2008@gmail.com
svaarthta@rediffmail.com
svaarthta2008@yahoo.com

Epaper :
epaper.swatantravarta.com

For Advertisement :
swadds1@gmail.com

क्या आप कब्जियत से परेशान हैं?

कब्ज का मुख्य कारण है अस्वस्थ जीवनशैली और गलत खान - पान, जो आगे जाकर बवासीर का कारण बन सकते हैं।



कब्ज

बवासीर

बैद्यनाथ नागपुर अभयामृत

स्वस्थ पाचन रहेगा, तभी तो स्वस्थ जीवन रहेगा।

कब्ज से लंबी राहत प्रदान करें।

बवासीर से सम्बंधित तकलीफें दूर करने में मदद करें।

पाचनतंत्र को सुचारु रखें।

3-6 चम्मच + समभाग पानी =

दिन में दो बार भोजन के बाद

1 माह तक सेवन करें।

www.baidyanath.co

वैद्यकीय सलाह : 8448444935



अभयारिष्ट से अधिक प्रभावशाली।